01/2015

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

के सौजन्य से

सप्रू हाउस पेपर

भारत की इज़रायल नीति का बदलता स्वरूप

डा. अनूप कुमार गुप्ता

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली-110005

भारत की इज़रायल नीति का बदलता स्वरूप

डा. अनूप कुमार गुप्ता

भारत की इज़रायल नीति का बदलता स्वरूप

प्रथम संस्करण, 2015

कापीराइट © विश्व मामलों की भारतीय परिषद

आई. एस. बी. एनः 978-93-83445-28-8

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

लेखक और प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना पुस्तक के किसी भी हिस्से का किसी भी रूप में पुनः प्रकाशन, प्रसारण की अनुमति नहीं है।

इस पेपर में व्यक्त किये गये विचार परिषद के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली–110001, भारत
दूरभाष : +91-11-23317242, फैक्स: +91-11-23322710
www.icwa.in

मुद्रण
अल्फा ग्राफिक्स
6ए/1, डब्ल्यू.ई.ए, करोल बाग,
नई दिल्ली–110005
दूरभाष : 9312430311

विषय-सूची

प्रस्तावना	5
जिओनवाद एवं इज़रायल पर भारतीय विमर्श	5
फिलिस्तीन-अरब समर्थक नीति	17
इज़रायल नीति में परिवर्तन कारक	22
नयी इज़रायल नीति	25
मोदी सरकार और इज़रायल	31
बहुआयामी सम्बन्ध	38
निष्कर्ष	41

भारत की इज़रायल नीति का बदलता स्वरूप

डा० अनूप कुमार गुप्ता

प्रस्तावना

जिओनवादी आंदोलन के प्रति रुझान और इज़रायल से संबंध स्थापना का प्रश्न भारत की विदेश नीति और राजनय के इतिहास में एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। 14 मई 1948 में इज़रायल राज्य की स्थापना के लगभग 44 वर्षों बाद भारत ने जनवरी 1992 में इस देश से राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की थी। उत्तर–शीतयुद्ध काल में भारत–इज़रायल के मध्य सम्बन्धों की स्थापना और उनका परवर्ती विकास सामान्य रूप से पश्चिम एशिया और विशेष रूप से इज़रायल के प्रति भारत की परंपरागत नीति में आए महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। दो–पक्षीय राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के बाद से दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, कृषि आदि क्षेत्रों में करीबी संबंध विकसित हुए।[1] इज़रायल के साथ बहुआयामी पारस्परिक लाभदायक सम्बन्धों के विकास के साथ–साथ भारत ने फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण, ईरान एवं अन्य पश्चिम एशियायी देशों के साथ भी मित्रवत संबंध बनाए रखे हैं। इज़रायल से राजनयिक संबंधों के सामान्यीकरण के बाद भी भारत ने अपनी परंपरागत फिलिस्तीन समर्थक नीति को भी यथावत बनाए रखा है।

जिओनवाद एवं इज़रायल पर भारतीय विमर्श

सामान्य रूप से यह माना जाता है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जिओनवाद, इज़रायल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर सम्पन्न हुए

राजनीतिक विमर्श में एकरूपता या आम सहमति प्रतिबिंबित होती है। लेकिन इज़रायल पर विमर्श में एकरूपता की धारणा सच से परे है। इज़रायल पर भारतीय विमर्श में काफी विविधता और यहाँ तक कि परस्पर विरोधी चिंतनधारा देखने को मिलती है जो इस महत्वपूर्ण विमर्श में राजनीतिक–सामरिक बहुलवाद को प्रतिबिम्बित करती है। भारत में जिओनवाद और इज़रायल पर विमर्श की शुरुआत स्वतन्त्रता के पूर्व ही शुरू हो चुकी थी। इस राजनीतिक–सामरिक विमर्श में तीन चिंतन धाराएँ प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई। स्वतन्त्रता के समय जिओनवाद, इजरायल और फिलिस्तीन के प्रति नीति संबंधी प्रश्न के बारे में भारत के राजनीतिक–सामरिक चिंतन में कम से कम तीन प्रमुख रणनीति उभर कर सामने आई थी – यथा गांधीवादी, हिन्दू राष्ट्रवादी और साम्यवादी। इस विमर्श में जिओनवाद और इज़रायल के प्रति रुझान उसको देखने की दृष्टि और नजरिए पर आधारित है। इस विशेष दृष्टि या चश्मे के स्वरूप के अनुरूप ही भारतीय विमर्श में इजरायल और जिओनवाद के प्रति अलग–अलग धारणा बनी जिसने न केवल भारत–इज़रायल सम्बन्धों के स्वरूप और दिशा के बारे में विमर्श को प्रभावित किया बल्कि इज़रायल के प्रति अपनायी जाने वाली प्रस्तावित रणनीति और तत्संबंधी सामरिक और राजनयिक सुझावों को एक एक विशिष्ट आकार प्रदान किया। भारत के राजनीतिक–सामरिक समुदाय में इज़रायल को देखने के कई प्रिज्म हैं। इस प्रिज्म या लेंस की विशिष्ट संरचना के अनुरूप ही जिओनवाद और इजरायल के बारे एक विशिष्ट नजरिया या धारण ा उभरती है। यानि जैसा प्रिज्म का स्वरूप होगा वैसी ही जिओनवाद, इज़रायल, फिलिस्तीनी प्रश्न और इज़रायल–फिलिस्तीन संघर्ष के प्रति धारणा होगी और तदनुरुप इज़रायल और भारत–इजरायल संबंधो के प्रति सुझाई जाने वाली रणनीति का स्वरूप भी विशिष्ट और भिन्न होगा।

इज़रायल पर भारतीय विमर्श में पहली धारा गांधीवादी और नेहरूवादी नजरिए का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें जिओनवाद की विचारधारा

का समर्थन नहीं किया गया। इस प्रिज्म के मूल प्रतिनिधि विचारक एवं समर्थक के रूप में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को देखा जा सकता है। गांधी और नेहरू द्वारा इज़रायल राज्य की स्थापना के लिए जिओनवादी प्रयासों का समर्थन नहीं किया गया। इस प्रिज्म के अनुसार फिलिस्तीन को फिलिस्तीनियों का घर माना गया और फिलिस्तीन समर्थक नीति पर बल दिया गया। गांधीवाद और जिओनवाद पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है।[2] इस धारा में यहूदियों के प्रति सहानुभूति अवश्य व्यक्त की गयी लेकिन इज़रायल की स्थापना के लिए किए जाने वाले जिओनवादी प्रयासों का समर्थन नहीं किया गया था। महात्मा गांधी ने लंबे समय तक उत्पीड़न के शिकार रहे यहूदियों के प्रति सहानुभूति अवश्य व्यक्त की लेकिन यहूदियों के लिए नेशनल होमलेंड की आवाज से वे आकर्षित नहीं थे।[3] महात्मा गांधी जिओनवाद और उसकी आधारभूत अवधारणा से सहमत नहीं थे। जिओनवाद के प्रति अपने मत को व्यक्त करते हुए नबंवर 1938 में गांधीजी ने हरिजन में एक लेख में कहा कि "फिलिस्तीन की बिब्लिकल अवधारणा एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है।"[4] गांधीजी की धारणा थी कि जिओन भौगोलिक नहीं है बल्कि यह ह्रदय में स्थित है। जिओनवाद के आधारभूत तर्क को खंडित करते हुए गांधीजी ने प्रश्न पूछा कि "पृथ्वी के अन्य लोगों की तरह वे (यहूदी) उसी देश को अपना घर क्यों नहीं बनाते जहां वे पैदा हुए हैं और जीविका अर्जन करते है?"[5] फिलिस्तीन में अरब समर्थक नीति अपनाते हुए गांधीजी ने कहा कि "फिलिस्तीन अरबों का उसी तरह है जैसे इंगलेंड अंग्रेजों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का। अरबों पर यहूदियों का आरोपण गलत और अमानवीय होगा।"[6] यहूदियों को सुझाव देते हुए गांधीजी ने कहा कि "वे केवल अरबों की सद्भावना पर फिलिस्तीन में बस सकते हैं। उनको अरबों का ह्रदय परिवर्तन की कोशिश करना चाहिए।" स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जिओनवाद के प्रति धारणा लगभग महात्मा गांधी के विचारों के ही अनुरूप थी। जिओनवाद के कई आलोचकों के विपरीत नेहरूजी फिलिस्तीन में यहूदी जड़ों

को अवश्य जानते थे लेकिन उनका यह भी कहना था कि बालफोर घोषणा के समय 'यह क्षेत्र खाली और नाबाद नहीं था' और यह इस समय 'किसी और का घर था।' इसीलिए नेहरू का कथन था कि "हमें याद रखना चाहिए कि फिलिस्तीन मूलतः अरब देश है और ऐसा ही बना रहना चाहिए।"[7] यह प्रिज्म ब्रितानी साम्राज्य के विरोध में था और चूंकि जिओनवादी आंदोलन को ब्रिटेन ने समर्थन दिया था इसलिए जिओनवाद का विरोध एक उप–सिद्धान्त के रूप में विकसित हुआ। इसीलिए इस प्रिज्म के अनुसार जिओनवादियों को परोक्ष सलाह देते हुए कहा गया कि यहूदियों को ब्रितानी सरकार का समर्थन नहीं लेना चाहिए बल्कि फिलिस्तीनी सद्भावना और समर्थन को पाने की कोशिश करना चाहिए। 1938 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने दिल्ली बैठक में कहा कि ब्रिटेन को यहूदी और अरबों को इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से निपटने के लिए छोड़ देना चाहिए। फिलिस्तीन प्रश्न के समाधान के लिए नेहरू ने 'एक राज्य' समाधान का सुझाव दिया था जिसके अनुसार ब्रिटेन को अपने पीछे फिलिस्तीन में एक सामासिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र छोड़ना चाहिए जिसमें अरब और यहूदी दोनों ही शामिल होंगें और एक संघीय संविधान का निर्माण करेंगें जिसमें एक भाग में अरब बहुमत होगा और दूसरे भाग में यहूदी बहुमत होगा और दोनों एक दूसरे से एक संघीय राज्य के ढांचे में बंधें होंगें जिसका शासन सयुंक्त और लोकतान्त्रिक तरीके से अरबों और यहूदियों द्वारा एक साथ किया जाएगा।[8]

शुरुआत में यह धारा पूर्ण रूप से जिओनवाद और इज़रायल के विरोध में थी और इसमें फिलिस्तीन और अरब राष्ट्रवाद के समर्थन की नीति पर बल दिया गया था। इस गांधी–नेहरूवादी धारा का लंबे समय तक कांग्रेस दल द्वारा अनुसरण किया गया। इस धारा ने शुरू में इज़रायल की स्थापना का विरोध किया था और इसके अस्तित्व को मान्यता देने से भी इंकार किया था। परवर्ती कालखंड में इस धारा में संशोधन दृष्टिगोचर हुआ और इजरायल के अस्तित्व को मान्यता देने के साथ उससे सीमित

सम्बन्धों की स्थापना को स्वीकारोक्ति दी गयी। इजरायल से राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना और बहुआयामी सहयोग के समानान्तर इस धारा के समर्थकों द्वारा फिलिस्तीन मुद्दे का पुरजोर समर्थन किया गया। इज़रायली विमर्श के संबंध में इस प्रिज्म के तार्किक निष्कर्ष के रूप में इस धारा में जिओनवाद का विरोध, स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की मांग का पूर्ण समर्थन, इज़रायल से सीमित सम्बन्धों की स्थापना, और फिलिस्तीनियों के प्रति इज़रायली व्यवहार की आलोचना पर बल दिया गया। इस धारा के कुछ समर्थक अरब–ईरान और फिलिस्तीन के प्रति कट्टर समर्थन व्यक्त करते हुए इज़रायल का तीव्र विरोध करते हैं। कांग्रेस के राज्य सभा सांसद मणि शंकर अय्यर के मत में इज़रायल से संबंध नैतिक रूप से संभव नहीं हैं और इस सदी के मध्य तक यहूदी राज्य का अस्तित्व नहीं रहेगा और फिलिस्तीन क्षेत्र फिलिस्तीनियों को मिल जाएगा।[9] मोदी सरकार की इज़रायल नीति का विरोध करते हुए अय्यर का मत है कि भारत के परंपरागत फिलिस्तीन–अरब समर्थक सैद्धान्तिक रुझान एवं मत को अब रक्षा सहयोग के प्रिज्म से देखे जाने के कारण रूपांतरित और विरूपित किया जा रहा है।[10] जुलाई 2014 में गाज़ा संघर्ष के दौरान मोदी सरकार की इज़रायल–फिलिस्तीन नीति की कटु आलोचना करते हुए अय्यर ने कहा कि इसने फिलिस्तीन पर ब्रिक्स प्रस्ताव के 'सुविधाजनक आवरण' को अपनाते हुए नेहरू को भुला दिया है।[11] जिओनवाद की उग्र हिन्दू राष्ट्रवाद से तुलना करते हुए अय्यर कहते हैं कि दोनों ही धर्म आधारित राष्ट्रवाद के समर्थक हैं इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की हिब्रू भाषा में बिनयामिन नेतान्याहु को 'मजाल तोव' कहकर बधाई दी थी। प्रकारांतर से अय्यर सुझाव देते हैं कि धर्मनिरपेक्ष भारत को मोदी सरकार कि इज़रायल नीति का समर्थन नहीं करना चाहिए और अरबों के साथ एकता दिखनी चाहिए।[12]

भारत में इज़रायल पर राजनीतिक–सामरिक विमर्श की दूसरी धारा हिन्दू राष्ट्रवाद और राजनीतिक यथार्थवाद से सम्बद्ध है जो जिओनवाद और

इज़रायल रूपी प्रति सकारात्मक रुझान को प्रतिबिम्बित करती। हिन्दू राष्ट्रवाद और राजनीतिक यथार्थवाद के दोनों ही प्रिज्म इज़रायल के प्रशंसक और उससे बेहतर संबंधो की स्थापना के समर्थक हैं। विनायक दामोदर सावरकर, सीताराम गोयल, अरुण शौरी जैसे कई हिन्दू विचारकों ने न केवल एंटि–सेमेटिज्म की कटु निंदा की बल्कि इज़रायल के निर्माण का कट्टर समर्थन किया। हिन्दू राष्ट्रवाद के प्रबल प्रवक्ता हिन्दू राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर थे।[13] सावरकर ने न केवल फिलिस्तीनी क्षेत्र में इज़रायल राज्य की स्थापना का पुरजोर समर्थन किया था बल्कि वे जिओनवाद और इज़रायल समर्थक नीति अपनाए जाने के भी पक्षधर थे। 1923 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'हिन्दुत्व' में सावरकर ने जिओनवाद समर्थक नीति पर बल दिया था। सावरकर के अनुसार "ऐतिहासिक रूप से इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि मुस्लिम पैगंबर के जन्म के दो हजार वर्ष पूर्व से ही सम्पूर्ण फिलिस्तीन यहूदियों का राष्ट्रीय गृह रहा है।" सावरकर ने फिलिस्तीन कहे जाने वाले क्षेत्र में यहूदी राज्य की स्थापना का पूर्ण समर्थन करते हुए बल देकर कहा कि "यदि जिओनवादी स्वप्न पूरा होता है, यदि फिलिस्तीन यहूदी राज्य बनता है, तो इससे हमें उतनी ही खुशी होगी जितनी हमारे यहूदी मित्रों को होगी।"[14] इस दूसरी धारा के अनुरूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इज़रायल का समर्थन करता है। स्वतन्त्रता के बाद स्वतंत्र दल और जनसंघ भी इज़रायल समर्थक नीति के पक्षधर थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी धारा के अनुरूप इज़रायल समर्थक रुख अपनाया। इस प्रकार 1992 के पूर्व भारत सरकार की अरब एवं फिलिस्तीन समर्थक नीति के बावजूद भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण तबका इजरायल का समर्थक था। भारत के सामरिक चिंतन में राजनीतिक यथार्थवादी धारा भी इजरायल से गहन संबंध का समर्थन करती है। इस धारा में न तो इज़रायल के प्रति कोई झिझक है और न ही उसका विरोध है बल्कि यह धारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत और इजरायल को स्वाभाविक साझेदार के रूप में देखती है। यह धारा भारत–इज़रायल दो–पक्षीय संबंधो को एक बहुआयामी लाभदायक

उच्च प्रोफाइल देने का समर्थन करती है। सुषमा स्वराज ने इजरायल को भारत के एक 'विश्वसनीय साझेदार' की संज्ञा दी थी। इस धारा के समर्थक आतंकवाद–निरोध के संदर्भ में भारत, अमरीका और इज़रायल के बीच एक गठबंधन का निर्माण करने का पुरजोर समर्थन करते हैं। इस प्रिज्म को व्यक्त करते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने भारत, इज़रायल और अमरीका के बीच एक सामरिक त्रिकोण की स्थापना का समर्थन करते हुए कहा था कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए स्वतंत्र समाजों का गठबंधन बनाया जाना चाहिए।[15] इसी धारा के अनुरूप डा० सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार इसिल यानि 'इस्लामिक स्टेट' द्वारा पैदा किए गए वैश्विक खतरे का निरोध करने में अपनी भिन्न–भिन्न क्षमताओं के कारण भारत, अमरीका और इज़रायल का विशेष उत्तरदायित्व है। स्वामी के अनुसार भारत के पास मानव संसाधन क्षमता है, अमरीका के पास अस्त्र क्षमता है और इज़रायल के पास खुफिया तंत्र क्षमता है। इस प्रिज्म के अनुरूप अपने एक भाषण में स्वामी ने कहा भारत सरकार को इसिल के खिलाफ लड़ाई में अमरीका का पूर्ण समर्थन करना चाहिए। हमास और इज़रायल के बीच संघर्ष को डा० स्वामी धार्मिक नजरिए से व्याख्यायित करने की बजाय आतंकवाद और लोकतान्त्रिक राज्य के बीच में एक संघर्ष के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि इज़रायल का पूर्ण समर्थन करना भारत के राष्ट्र हित में है। स्वामी के अनुसार भारत के राष्ट्रवादी मुसलमानों को हमास की बजाय इज़रायल का समर्थन करना चाहिए। इनके मत में भारत को सयुंक्त राष्ट्र संघ में भी इज़रायल का समर्थन करना चाहिए।[16]

भारत में इज़रायल संबंधी सामरिक चिंतन एवं विमर्श में तीसरी महत्वपूर्ण धारा साम्यवादी विचारधारा से जुड़ी हुई है जिसके समर्थक भारत के साम्यवादी दल हैं जो जिओनवाद और इज़रायल के कट्टर आलोचक है तथा फिलिस्तीन आंदोलन के पुरजोर समर्थक हैं। यह धारा स्वतंत्र एवं संप्रभु फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की समर्थक है

और इज़रायल की फिलिस्तीन नीति की कट्टर विरोधी है। इस धारा में जिओनवाद को मार्क्सवाद–लेनिनवाद[17] के प्रिज्म से व्याख्यायित करते हुए इसका तीव्र वैचारिक विरोध किया गया और फिलिस्तीन समर्थक नीति पर बल देते हुए जिओनवाद और इज़रायल की कटु आलोचना की गयी। मार्क्सवादी–लेनिनवादी विचारधारा ने शुरू से ही जिओनवाद का विरोध किया था। कार्ल मार्क्स के लेखन विशेषकर उनकी कृति "यहूदी समस्या का भौतिकवादी विश्लेषण" में जिओनवाद विरोधी विचारों की जड़ों को देखा गया है।[18] वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स ने 'यहूदी' शब्दाबली को बुर्जुआ समाज और प्रकारांतर से पूंजीवाद के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया था और यहूदियों की समस्या का मूल कारण उनकी आर्थिक भूमिका को माना था और इसीलिए मार्क्स की नजर में यहूदी प्रश्न का समाधान एक वर्गविहीन समाजवादी समाज में यहूदियों के घालमेल यानि असिमिलेशन में निहित है जिसमें लाभ की प्रेरणा के लिए कोई स्थान नहीं होगा।[19] इसी धारा के अनुरूप रूसी साम्यवादी नेता व्लादिमीर लेनिन ने 1903 में साम्यवादी दल के मुखपत्र 'इस्करा' में लिखा था कि यहूदी राष्ट्रवाद का मूल विचार स्पष्टतः प्रतिक्रियावादी और यहूदी सर्वहारा–वर्ग के विरोध में है।[20] इसी अवधारणा के आधार पर सोवियत संघ ने जिओनवाद का तीव्र विरोध किया तथा अरब राष्ट्रवाद का समर्थन किया था।[21] भारत के साम्यवादी दलों ने मार्क्सवाद–लेनिनवाद की चिंतनधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए और इसके अनुरूप जिओनवाद और इज़रायल के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है। साम्यवादी विचारधारा पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का कट्टर विरोध करती है और चूंकि इसके अनुरूप अमरीका, जिओनवाद और इज़रायल मूलतः बुर्जुआ समाज, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद से सम्बद्ध है अतः अमरीका, जिओनवाद और इज़रायल का विरोध इस धारणा की तार्किक परिणति है। इस धारा में फिलिस्तीन आंदोलन का समर्थन करते हुए जिओनवादियों द्वारा 14 मई 1948 को इज़रायल राज्य की स्थापना को एक बलात प्रयास माना गया। साम्यवादी धारा फिलिस्तीनियों के प्रति इज़रायली नीति का तीव्र

विरोध करती है।[22] मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने जुलाई 2014 में गाज़ा पट्टी में इजरायली सैनिक कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए हमलों को तत्काल बंद करने की मांग की और मोदी सरकार पर अन्यायपूर्ण इज़रायली कार्रवाही को अनदेखा करने और इज़रायल समर्थक रुख अपनाने का आरोप लगाया।[23] इस गाज़ा संघर्ष के दौरान साम्यवादी नेता सीताराम येचुरी ने मांग की थी कि भारत को गाज़ा में इज़रायल की सैन्य कार्रवाई की कड़ी आलोचना करनी चाहिए। इज़रायल की फिलिस्तीनी नीति के विरोध में आर्थिक पहलू को व्यक्त करते हुए येचुरी की धारणा है कि भारत ने इज़रायल से हथियारों को खरीदकर फिलिस्तीन पर इज़रायल के अमानवीय युद्ध का वित्तीय समर्थन किया है इसलिए भारत को फिलिस्तीनियों के साथ सुद्रढ़ता को व्यक्त करने के लिए इज़रायल से सैन्य सहयोग यदि समाप्त नहीं तो कम से कम निलंबित अवश्य कर देना चाहिए।[24] प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित इज़रायल यात्रा का विरोध करते हुए माकपा के मुखपत्र 'पीपुल्स डेमोक्रेसी' ने इसे स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के समर्थन की भारत की पुरानी नीति के अंत के रूप में व्याख्यायित किया।[25] इस प्रिज्म का सुझाव है कि भारत को अमरीका की ग्लोबल रणनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि अमरीकी रणनीति चीन के अवरोध पर आधारित है। इस प्रिज्म के अनुसार अमरीका और इजरायल एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि यह एक ओर इज़रायल को अमरीकी रणनीति का समर्थक मानता है और दूसरी ओर यह अमरीका को इज़रायल की अन्यायपूर्ण और दमनकारी कुख्यात फिलिस्तीनी नीति का समर्थक करार देता है क्योंकि अमरीकी समर्थन के कारण ही इजरायल फिलिस्तीनी अरब क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए है। इस प्रिज्म ने आतंकवाद निरोध पर आधारित अमरीका, इज़रायल और भारत के बीच प्रस्तावित किसी भी तरह के सामरिक त्रिकोणीय गठबंधन का तीव्र विरोध करते हुए बाजपेयी सरकार पर इस सामरिक त्रिकोण की तरफ अग्रसर होने और अमरीकी ग्लोबल रणनीति का हिस्सा बनने का आरोप लगाया।[26] इस प्रिज्म के

अनुसार इज़रायल के साथ सैन्य और सुरक्षा सहयोग में बढ़ती गहनता भारत मूलभूत हितों के लिए घातक है इसलिए भारत को इज़राइली गुप्तचर उपग्रह के प्रक्षेपण को बंद कर देना चाहिए और इजरायल से सैन्य सहयोग समाप्त कर देना चाहिए।[27]

इस प्रकार भारत के राजनीतिक–सामरिक समुदाय में जिओनवाद और इज़रायल पर विमर्श पर एक विविधता देखने को मिलती है। इस विमर्श में गांधी–नेहरूवादी प्रिज्म की रणनीति जिओनवाद का विरोध और अरब राष्ट्रवाद के समर्थन पर आधारित थी। हिन्दू राष्ट्रवाद और राजनीतिक यथार्थवाद का रणनीतिक प्रिज्म जिओनवाद और फिलिस्तीन में यहूदियों के नेशनल होमलेंड की स्थापना का पक्षधर था। यह प्रिज्म इज़रायल से करीबी संबंध स्थापित करने पर ज़ोर देता है। फिलिस्तीनी आंदोलन के कट्टर समर्थन एवं जिओनवाद और इज़रायल के प्रति नकारात्मक रुझान में साम्यवादी प्रिज्म काफी हद तक गांधी–नेहरूवादी प्रिज्म के समीप अवश्य था लेकिन साम्यवादी प्रिज्म में तुलनात्मक रूप से जिओनवाद और इज़रायल के विरोध की तीव्रता अधिक थी। गांधी–नेहरूवादी प्रिज्म और साम्यवादी प्रिज्म में फिलिस्तीन नीति पर साम्यता के बावजूद दोनों के वैचारिक आधार में काफी अंतर था। इन दोनों प्रिज्मों में जिओनवाद और इज़रायल के विरोध तथा फिलिस्तीन के समर्थन के लिए प्रस्तुत की गयी तार्किक प्रतिज्ञप्तियों के विचारधारात्मक ढांचे में मूलभूत अंतर था।

आचार्य चाणक्य द्वारा 'अर्थशास्त्र' में वर्णित मण्डल सिद्धान्त और षाड्गुण्य नीति के नजरिए से भारत में इज़रायल पर राजनीतिक–सामरिक विमर्श संबंधी उपरोक्त तीनों प्रिज्म का तुलनात्मक विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धान्त निर्माण एवं ग्रेंड रणनीति के निर्माण में प्राचीन भारत के राजनीतिक–सामरिक चिंतक आचार्य चाणक्य की 'अर्थशास्त्र' एक महत्वपूर्ण प्रस्थान विंदु है।[28] चाणक्य ने पड़ोसी राज्यों के प्रति नीति के संदर्भ में मण्डल सिद्धान्त और विदेश नीति के छ्ह विकल्प के रूप में षाड्गुण्य नीति को प्रस्तुत किया था।[29] इजरायल संबंधी विमर्श

में गांधी–नेहरुवादी प्रिज्म में फिलिस्तीन और अरब राज्यों को एक मित्र के रूप में माना गया है और विदेश नीति विकल्प के रूप में फिलिस्तीन और अरब राज्यों को चाणक्य नीति के अनुरूप संधि रणनीति की इकाई के रूप में तो नहीं लेकिन करीबी राजनीतिक–सामरिक मित्र के रूप में अवश्य देखा गया है। अरब–इज़रायल संघर्ष और युद्ध में इस प्रिज्म ने अरब राज्यों का राजनीतिक और राजनयिक समर्थन किया। इस प्रिज्म में इज़रायल को प्रत्यक्ष रूप से चाणक्य द्वारा प्रस्तावित अरि यानि शत्रु की श्रेणी में तो नहीं माना गया लेकिन इसे एक मित्र राज्य के रूप में भी नहीं देखा गया और इज़रायल की फिलिस्तीनी नीति का पुरजोर विरोध किया गया और प्रकारांतर से इज़रायल का भी विरोध किया गया। वहीं दूसरी ओर हिन्दू राष्ट्रवादी और राजनीतिक यथार्थवादी प्रिज्म में चाणक्य के मण्डल नेरेटिव के अनुरूप इज़रायल को एक स्वाभाविक मित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया और चाणक्य के षाड्गुण्य नीति के प्रारूप के संदर्भ में इज़रायल से सामरिक गठबंधन की स्थापना की रणनीति को अपनाने का सुझाव प्रस्तावित किया गया। 2003 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बृजेश मिश्रा द्वारा आतंकवाद–निरोध के संदर्भ में अमरीका, इज़रायल और भारत के बीच सामरिक गठबंधन स्थापना का जो सुझाव दिया गया था उसे आधुनिक संदर्भों में चाणक्य की संधि रणनीति के समकक्ष रखा जा सकता है। इस यथार्थवादी प्रिज्म में फिलिस्तीन को न तो मित्र माना गया है और न ही शत्रु बल्कि एक प्रकार से तटस्थता के भाव को प्रदर्शित किया गया है। यह प्रिज्म चरमपंथी फिलिस्तीनी संगठन हमास का विरोधी है और हमास–इज़रायल संघर्ष में इज़रायल का समर्थन करता है। इज़रायल विमर्श पर साम्यवादी प्रिज्म में जिओनवाद और इज़रायल को लगभग अरि के रूप में देखा गया है और फिलिस्तीन को मित्र माना गया है। इस प्रिज्म में इज़रायल की फिलिस्तीनी नीति का पुरजोर विरोध किया गया है और इज़रायल से सैन्य–सामरिक सहयोग को समाप्त करते हुए इज़रायल से संभावित किसी भी गठबंधन का पुरजोर विरोध किया गया है। यह प्रिज्म फिलिस्तीन को पूर्ण समर्थन की नीति पर बल देता है।

इस प्रकार जिओनवाद और इज़रायल पर विमर्श में राजनीतिक–सामरिक बहुलवाद के अस्तित्व के बावजूद एक राज्य–कर्ता के रूप में स्वतंत्र भारत की इज़रायल नीति और तत्संबंधी राजनयिक व्यवहार में गांधी–नेहरूवादी प्रिज्म का प्रभाव काफी लंबे समय तक बना रहा। इस नीति में फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इज़रायल से राजनीतिक–सामरिक दूरी बनाए रखी गयी। तत्कालीन नेतृत्व द्वारा अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और आंतरिक संरचनात्मक बाध्यताओं के परसेपशन और गांधी–नेहरूवादी प्रिज्म के प्रभाव के आधार पर आजाद भारत में इसी प्रिज्म के अनुरूप इज़रायल नीति को विकसित किया गया था। परवर्ती कालखंड में इज़रायल से करीबी संबंध स्थापित करने की समर्थक हिन्दू राष्ट्रवाद और यथार्थवाद के प्रिज्म और तत्संबंधी रणनीति के समर्थन में स्वतंत्र दल, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर आवाज उठाई और इज़रायल नीति के संबंध में सामरिक विमर्श को आगे बढ़ाते हुए भारत की इज़रायल नीति में संशोधन की मांग की और इज़रायल समर्थक विदेश नीति को अपनाने पर बल दिया गया। 1992 में भारत की इज़रायल नीति को संशोधित किया गया और दोनों देशों में राजनयिक संबंधो की स्थापना की गयी। इस समय तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, पश्चिम एशिया की राजनीति में काफी संरचनात्मक बदलाव भी आ चुके थे। इस प्रकार भारत की संशोधित इज़रायल नीति में सांस्कृतिक यथार्थवाद[30] द्वारा प्रस्तावित सामरिक संस्कृति उपागम के अनुरूप आंतरिक राजनीतिक पर्यावरण के यथार्थवादी राजनीतिक–सामरिक चिंतन एवं प्रिज्म का कदाचित प्रभाव अवश्य था लेकिन साथ ही संरचनात्मक यथार्थवाद[31] के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पर्यावरण की संरचनात्मक बाध्यताओं ने भी इस नीति पर प्रभाव डाला था। इज़रायल के समर्थन संबंधी प्रिज्म के बढ़ते प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा आंतरिक पर्यावरण की संरचनात्मक बाध्यताओं के अनुरूप समायोजन करते हुए भारत की इज़रायल नीति में 1992 में संशोधन किया गया हालांकि फिलिस्तीन–अरब समर्थन की परंपरागत नीति को यथावत बनाए रखा गया।

फिलिस्तीन-अरब समर्थक नीति

भारत–इज़रायल राजनयिक सम्बन्धों के विकास का इतिहास बड़ा ही रोचक है। भारत–इज़रायल संबंध एक दूरस्थ अजनबी के लंबे दौर से गुजरने के बाद सम्बन्धों में सामान्यीकरण से होते हुए बहुस्तरीय लाभदायक साझेदार के मुकाम तक पहुंचे हैं।[32] शुरुआत में भारत की नीति अरब–फिलिस्तीन समर्थक और जिओनवाद एवं इज़रायल विरोधी थी। इस समय भारतीय नेतृत्व ने जिओनवाद और यहूदियों के लिए नेशनल होमलेंड की स्थापना के प्रयासों का समर्थन नहीं किया था। जिओनवाद और अरब राष्ट्रवाद के टकराव में भारत ने अरब राष्ट्रवाद के समर्थन की नीति अपनाई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप के यहूदियों ने फिलिस्तीन कहे जाने वाले क्षेत्र पर 'नेशनल होमलेंड' की स्थापना के लिए जिओनवादी आंदोलन की शुरुआत की थी। राजनीतिक जिओनवाद के जनक थियोडोर हर्जल थे। जिओनवादी राजनय अपने भावी राज्य की स्वीकार्यता के लिए प्रयासरत था। 1917 में ब्रिटेन सरकार द्वारा बालफोर घोषणा के माध्यम से फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदियों के लिए नेशनल होमलेंड की स्वीकृति जिओनवादियों के राजनयिक प्रयासों के लिए एक बड़ी सफलता थी। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रवादी नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और विदेश नीति पर अपनी राय स्पष्ट रूप से रखी थी। इस समय भारत ने पश्चिम एशिया में अरब समर्थक नीति अपनाई थी। खिलाफत आंदोलन की मांग के समर्थन में महात्मा गांधी ने मार्च 1921 में एक वक्तव्य में फिलिस्तीन पर मुस्लिम नियंत्रण बने रहने की बात की थी।[33]

अब यहूदी राजनय ने अपने जिओनवादी लक्ष्यों पर राजनयिक समर्थन पाने के लिए भारत पर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया। जिओनवादियों ने भारतीय राष्ट्रवादी नेतृत्व से संपर्क साधा और इज़रायल राज्य की स्थापना के लिए समर्थन मांगा। 20वीं सदी के तीसरे दशक से ही भारत की जिओनवाद और भावी इज़रायल नीति का संकेत स्वतन्त्रता आंदोलन

के समय से ही राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रभावी तरीके से दिया गया था। महात्मा गांधी ने इस मुद्दे पर 1938 में अपनी राय सार्वजनिक रूप से रखी। दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान गांधीजी के कुछ यहूदी मित्र भी बने थे जिनमे हेनरी पोलक और हरमन कालेनबाख प्रमुख थे। यहूदी नेता मोशे शेरतोक के निवेदन पर हरमन कालेनबाख ने मई 1937 में भारत आकर गांधीजी से मुलाक़ात कर जिओनवाद के लिए समर्थन मांगा। हरमन कालेनबाख इस समय तक जिओनवादी हो चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आंग्ल–यहूदी सांसद सिडनी सिलवरमेन और अमरीकी यहूदी जीवनीकार लुइस फिशर ने गांधीजी से मुलाक़ात की थी। ज्यूईश वर्चुअल लाइब्रेरी द्वारा एक लेख में यह दावा किया गया कि इन लोगों से मुलाक़ात में गांधीजी ने व्यक्तिगत रूप से जिओनवाद का समर्थन किया था लेकिन उसे कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया।[34] सार्वजनिक रूप से गांधीजी ने जिओनवाद का समर्थन नहीं किया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गांधीजी की नीति का ही अनुसरण किया था। 13 जून 1947 में प्रसिद्द वैज्ञानिक अलवर्ट आइन्स्टाइन ने नेहरुजी को पत्र लिखकर इज़रायल के प्रति नीति बदलने का अनुरोध किया था।[35] लेकिन आइन्स्टाइन के तर्क नेहरूजी को आश्वस्त न कर सके।

इस समय तक फिलिस्तीन क्षेत्र में तनाव बहुत अधिक बढ़ चुका था। सयुंक्त राष्ट्र संघ ने ब्रिटिश मेंडेट के अधीन फिलिस्तीन क्षेत्र पर यहूदियों और फिलिस्तीनियों के दावे पर विचार कर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया और 29 नवंबर 1947 को इस क्षेत्र में यहूदियों और फिलिस्तीनियों के लिए पृथक–पृथक राज्य की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 33, विपक्ष में 13 मत पड़े थे जब कि 10 राज्य अनुपस्थित रहे थे। ब्रिटिश मेंडेट की समाप्ति की पूर्व संध्या पर 14 मई 1948 को इज़रायल राज्य के उदय की घोषणा की गयी। सोवियत संघ इज़रायल को विधिक मान्यता देने वाला पहला देश बना।

सयुंक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन मुद्दे पर विभाजन मतदान के दो दिन पूर्व जिओनवादियों ने नेहरू का समर्थन पाने की एक और कोशिश की। वाइज़मेन ने एक केबिल में नेहरू को लिखा कि वे 'समझ नहीं सकते कि भारत कैसे विभाजन योजना का विरोध कर सकता है।'[36] भारत ने सयुंक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के बंटवारे के प्रस्ताव के विरोध में मत दिया था। भारत ने शुरूआत से ही अरब एवं फिलिस्तीन समर्थक नीति अपनायी थी। फिलिस्तीन समर्थन की भारत की नीति इज़रायल से राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के बाद भी जारी बनी रही।

इज़रायल की स्थापना के साथ ही प्रथम अरब–इज़रायल युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1949 में भारत ने सयुंक्त राष्ट्र में इज़रायल के प्रवेश का विरोध किया। इज़रायल नीति में थोड़ा परिवर्तन लाते हुए भारत ने सितंबर 1950 में इज़रायल के अस्तित्व को स्वीकार किया। लेकिन राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना नहीं की। भारत ने बंबई में इज़रायल को वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी। इस प्रकार इज़रायल से सम्बन्धों को काफी कम रखते हुए सीमित सम्बन्धों की नीति पर बल दिया गया।

अरब–इज़रायल संघर्ष में भारत ने अरब राज्यों का समर्थन किया था। मिस्र और उसके नेता अब्देल जमाल नासिर के साथ भारत के करीबी संबंध विकसित हुए।[37] 1956 के स्वेज़ संकट के समय भारत ने मिस्र पर इज़रायली हमले की आलोचना की। इस समय भारत–इज़रायल सम्बन्धों में गिरावट आई। जून 1967 के छ्ह दिवसीय अरब–इज़रायल युद्ध में भारत ने अरब देशों का पक्ष लिया और इज़रायल पर दोषारोपण किया। उल्लेखनीय है कि इस समय भारतीय राजनीति में स्वतंत्र दल और जन संघ ने इज़रायल समर्थक नीति पर बल दिया। 1973 के योम किप्पूर युद्ध में भी भारत ने मिस्र और सीरिया का समर्थन किया। हालांकि इस समय युद्ध की शुरुआत मिस्र और सीरिया ने की थी लेकिन भारत का मानना था कि इस क्षेत्र में तनाव का कारण इज़रायल द्वारा अधिग्रहीत अरब क्षेत्रों को खाली करने से मना करना है।

1977 में सत्ता में आयी जनता सरकार इज़रायल से राजनयिक सम्बन्धों को सामान्य करना चाहती थी पर संभवतः अरब नाराजगी के कारक के कारण ऐसा न कर सकी। जनवरी 1979 में इज़रायली रक्षा मंत्री मोशे दयान ने भारत यात्रा की लेकिन भारत–इज़रायल सम्बन्धों के सामान्यीकरण की दिशा में कोई ठोस प्रगति न हो सकी। 1979 में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद अरब समर्थन की नीति जारी रही। इस समय भारत ने इज़रायल द्वारा 1967 में अधिग्रहीत किए गए क्षेत्रों को खाली करने की फिलिस्तीनी मांग का समर्थन किया। 1982 में लेबनान पर इज़रायली हमले की भारत ने कटु आलोचना की। 1982 में ही बंबई में इज़रायली वाणिज्य–दूत योसेफ हसीन की भारत की अरब समर्थक नीति पर टिप्पणी को आपत्तिजनक मानते हुए सरकार द्वारा उन्हे निष्कासित कर दिया था।

जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो इज़रायल के प्रति भारत की नीति का पुनः मूल्यांकन करने की पहल शुरू हुई। 1985 में संयुक्त राष्ट्र के सत्र के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बहुचर्चित दूरगामी मुलाक़ात हुई। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अमरीका यात्रा के दौरान अमरीकी कांग्रेस के सदस्य के निवेदन पर प्रमुख यहूदी लौबिस्ट से मुलाक़ात हुई थी। इसके बाद ही नवीन इज़रायली वाणिज्य दूत की भारत में वापसी की जा सकी। इस समय इज़रायल में इंतिफ़ादा के रूप में स्वतः स्फूर्त फिलिस्तीनी हिंसक प्रतिरोध उभार पर था। जिनेवा में एक बैठक में भारत के विदेश राज्य मंत्री केके तिवारी ने इज़रायल की आलोचना से बचते हुए फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ–साथ इज़रायल के शांति और सुरक्षा में रहने के अधिकार को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू की गयी इज़रायल के साथ सम्बन्धों के मूल्यांकन नीति और इज़राइली नेतृत्व और यहूदी व्यक्तियों से राजनयिक मुलाकातों और संपर्कों ने जनवरी 1992 में इज़रायल से सम्बन्धों के सामान्यीकरण की आधारशिला रखी।

भारत ने शुरू से ही फिलिस्तीन समर्थन की नीति अपनायी थी। 1973 के अरब–इज़रायल युद्ध के बाद फिलिस्तीनी मुद्दा तेजी से उभरा और भारत ने पीएलओ के समर्थन की नीति अपनायी। जहां एक ओर भारत ने फिलिस्तीनी समर्थक नीति के तहत सयुंक्त राष्ट्र में पीएलओ के ओब्जर्बर दर्जे का समर्थन किया वहीं इज़रायल विरोधी रुख अपनाते हुए जिओनवाद को नस्लवाद के समान मानने वाले प्रस्ताव का भी समर्थन किया। 1975 में भारत ने पीएलओ को मान्यता दी एवं 1980 में इससे पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की और दिल्ली में पीएलओ मिशन को दूतावास का दर्जा दिया गया। नवंबर 1988 में भारत ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी। 1993 में ओस्लो समझौते के बाद भारत ने गाज़ा में अलग से भारतीय मिशन खोला जिसे 2004 में पश्चिमी तट के रमल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया। 2012 में भारत ने सयुंक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें फिलिस्तीनीयों को 'गैरसदस्य पर्यवेक्षक राज्य दर्जा' का स्तर दिया गया।

भारत की अरब–फिलिस्तीन समर्थन एवं इज़रायल से दूरी बनाए रखने की नीति के कई कारण थे। इज़रायल के उदय के साथ ही अरब–इज़रायल संघर्ष की शुरुआत हुई थी। इस समय भारत न तो जिओनवाद का समर्थन कर सकता था और न ही अरब–इज़रायल संघर्ष में तटस्थता या इज़रायल समर्थक नीति अपना सकता था। साम्राज्यवाद विरोधी और अफ्रीका–एशिया भ्रातत्व की नीति पर बल देने के कारण भारत ने अरब राष्ट्रवाद का समर्थन किया। चूंकि इज़रायल के उदय में ब्रिटेन का समर्थन था और भारतीय नेतृत्व अँग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलनरत था अतः इस आधार पर भी जिओनवाद का विरोध किया गया था। अरब समर्थन और जिओनवाद विरोध की भारत की नीति का आधार सिर्फ नैतिक और विचारधारात्मक ही नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन के पत्र का जवाब देते हुए 11 जुलाई 1947 को नेहरू ने विदेशनीति के यथार्थवादी पहलू को उजागर करते हुए लिखा था कि "प्रत्येक देश

अपने हितों के बारे में सर्वप्रथम सोचता है...अक्सर ऐसा होता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय नीति किसी देश की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप होती है तो वह राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बेहतरी के लिए साहसी भाषा अपनाता है। लेकिन ज्यों ही वह अंतर्राष्ट्रीय नीति राष्ट्रीय हितों या स्वार्थपरिता के विरोध में प्रतीत होती है तो उस अंतर्राष्ट्रीय नीति का अनुसरण न करने के कई कारण हो सकते हैं।"[38] इस प्रकार नेहरू भारत की फिलिस्तीन समर्थन की नीति को देश के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप मान रहे थे। वस्तुतः पश्चिम एशिया से तेल की आपूर्ति का प्रश्न नवोदित भारत के विकास एवं अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण था। साथ ही पाकिस्तान से संघर्ष और कश्मीर मुद्दे पर भारत को अरब–मुस्लिम देशों के समर्थन या कम से कम उनकी तटस्थता की आवश्यकता थी। इस समय कश्मीर का मुद्दा सयुंक्त राष्ट्र संघ में था और भारत को अरब देशों के समर्थन की जरूरत थी। यह सच है कि कालांतर में पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर भारत को अरब देशों का अपेक्षित समर्थन नहीं मिला था लेकिन नवोदित भारत अरब देशों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। विभाजन की त्रासदी के तत्काल बाद भारत की जनांककीय संरचना के स्वरूप के तत्व को भारत की अरब नीति निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाने से इंकार नहीं किया जा सकता। भारत के बहुत से लोग पश्चिम एशिया में जीविका एवं अर्थोपार्जन के लिए रहते हैं और इनसे देश को रीमिटान्स के रूप में विदेशी मुद्रा मिलती है। लेकिन समय की चाल बदली और तदनुरूप भारत की इज़रायल नीति में भी बदले पर्यावरण का प्रतिबिंब झलका। अंततः 29 जनवरी 1992 को उदीयमान नवीन परिवेश में भारत द्वारा इज़रायल से राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की घोषणा की गयी।

इज़रायल नीति में परिवर्तन कारक

भारत द्वारा इज़रायल से राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना अचानक शून्य में नहीं की गयी थी। अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और आंतरिक कारकों ने

भारत–इज़रायल सम्बन्धों में बदलाव की पीठिका तैयार की थी। 20वीं सदी का अंतिम दशक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन के दौर का साक्षी बना था। शीत युद्ध के अंत और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात एक–ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ था। अब अमरीका विश्व में एकमात्र शक्ति बनकर उभरा था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विचारधारा के आग्रहों से मुक्त हो चुके थे। सोवियत संघ भारत का करीबी मित्र था और इसका विघटन भारत के लिए राजनयिक–सामरिक नुकसान था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रीय हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत को नए मित्रों की जरूरत थी। जटिल दो–ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थान पर इस उदीयमान चुनौतीपूर्ण एक–ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय संरचना में भारत द्वारा अमरीका से दो–पक्षीय संबंधो को पुनरपरिभाषित करना एक सामरिक आवश्यकता थी। भारत–अमरीका सम्बन्धों में दोनों देशों की विदेश नीति उद्देश्यों में भिन्नता के साथ–साथ इज़रायल कारक एक महत्वपूर्ण तत्व था। इज़रायल से राजनयिक संबंधो की स्थापना भारत को न केवल अमरीका के करीब ला सकती थी बल्कि रक्षा, कृषि एवं तकनीक के क्षेत्र में इज़रायली विशेषज्ञता से जरूरतमन्द सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकती थी। इसी समय भारत ने 'लुक ईस्ट नीति' अपनाकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से भी करीबी संबंध बनाने की नीति अपनाई।

एक क्षेत्र की दृष्टि से पश्चिम एशिया की राजनीति में भी महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे। अब तक इज़रायल के कट्टर विरोधी रहे फिलिस्तीनी संगठन पीएलओ ने 1988 में इज़रायल के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था। अमरीका ने पीएलओ से वार्ता शुरू कर दी थी। खाड़ी युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में इज़रायल–फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया की शुरुआत हो रही थी। मेड्रिड में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था और आशा की जा रही थी कि अब फिलिस्तीन मुद्दे का शीघ्र ही समाधान हो जाएगा। जिओनवादी विचारधारा और इज़रायल के विरोधी रहे फिलिस्तीन और अरब समर्थक सोवियत संघ ने भी अक्तूबर 1991 में इज़रायल से

पुनः राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना कर ली थी। अंतर–राज्य संघर्ष के रूप में अरब–इज़रायल संघर्ष समाप्त भले ही न हुआ हो लेकिन इसमें एक 'गिरावट' जरूर आ रही थी। 1978 में इज़रायल–मिस्र के बीच केंप डेविड समझौते के बाद 1979 में दोनों देशों के मध्य एक शांति संधि हुई जिसमें मिस्र ने सिनाई प्रायद्वीप की इज़रायल से वापसी के एवज में इसके अस्तित्व को स्वीकार किया था। पीएलओ के नेता यासिर अराफात द्वारा भारत–इज़रायल संबंधो के सामान्यीकरण पर अपना सकारात्मक रुख व्यक्त करने के बाद भारत के लिए इज़रायल नीति में परिवर्तन करना सहज था। इज़रायल–फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया में भारत की किसी भी सार्थक भूमिका के लिए जरूरी था कि इज़रायल से सम्बन्धों का सामान्यीकरण कर राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की जाय।

भारत के आंतरिक आर्थिक एवं राजनीतिक पर्यावरण में भी परिवर्तन आया था। भारत ने 1990 की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनायी थी। इस समय भारत को आईएमएफ और विश्व बैंक के समर्थन की जरूरत थी। इन दोनों संस्थाओं में अमरीकी प्रभाव को देखते हुए भारत को अमरीका के सहयोग की आवश्यकता थी। भारत–अमरीका सम्बन्धों के नवीन समीकरण में भारत के इज़रायल से सम्बन्धों के सामान्यीकरण के प्रश्न का हल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता था। यह एक संयोग हो या सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव की 1992 में अमरीका यात्रा के ठीक पूर्व ही इज़रायल से राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की घोषणा की गयी थी। साथ ही भारत में एक राजनीतिक वर्ग ऐसा भी उभर कर आया था जो इज़रायल से राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना का पक्षधर था। भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद महाजन, समाजवादी जनता पार्टी के यशवंत सिन्हा और जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने इज़रायल के प्रति भारतीय नीति में बदलाव की वकालत की थी। अब सत्ता के गलियारों में यह भी अहसास किया जाने लगा था कि इज़रायल से राजनीतिक

दूरी बनाए रखने और अरब–फिलिस्तीन समर्थक नीति अपनाए जाने के बावजूद भी भारत को पश्चिम एशिया के देशों से संकट के समय पाकिस्तान और कश्मीर मुद्दे पर अपेक्षित समर्थन नहीं मिला था। पश्चिम एशिया के अधिकतर देशों ने लगभग पाकिस्तान समर्थक नीति पर बल दिया था। 1969 के मुस्लिम देशों के रबात सम्मेलन में पाकिस्तान के दवाव के फलस्वरूप भारत के प्रति अपनाया गया सौतेला व्यवहार और 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर पश्चिम एशियायी देशों का राजनीतिक मौन भारत के लिए अप्रत्याशित था। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को अपनी रक्षा के लिए हथियारों की आपूर्ति के लिए नए स्रोतों की तलाश करनी थी। इज़रायल का सैन्य–औधौगिक संकुल भारत की रक्षा ररूरतों को पूरा करने में सक्षम था। भारत में उभरते आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए इज़रायल के अनुभव को साझा करने को एक अवसर के रूप में देखा गया। नए आर्थिक एवं भू–सामरिक परिवेश में सामरिक, रक्षा, आतंक–निरोध, कृषि, जल–प्रबंधन, विज्ञान एवं तकनीकी और आर्थिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इज़रायल से करीबी सम्बन्धों के विकास की संभावना को एक नए अवसर के रूप में देखा गया।

नयी इज़रायल नीति

इस परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और आंतरिक पर्यावरण में भारत ने अपनी विदेश नीति को समायोजित किया। 29 जनवरी 1992 को भारत सरकार द्वारा इज़रायल से राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की घोषणा के बाद भारत–इज़रायल संबंधों में एक नया दौर शुरू हुआ। भारत की परंपरागत पश्चिम एशिया नीति अरब–फिलिस्तीन समर्थन और इज़रायल विरोध पर आधारित थी और इज़रायल से सम्बन्धों के सामान्यीकरण के लिए फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान की शर्त लगाई गयी थी। नयी पश्चिम एशिया नीति में पुरानी नीति के इज़रायली घटक में आमूलचूल बदलाव का संकेत दिया गया शेष नीतिगत ढांचा लगभग यथावत बना रहा। अब फिलिस्तीन समर्थन की परंपरागत भारतीय नीति की निरंतरता

इज़रायल से गत्यात्मक एवं लाभदायक सम्बन्धों के विकास में बाधा नहीं थी। इस नयी नीति में दोनों मुद्दों को अलग–अलग कर दिया गया था। अब भारत की इज़रायल नीति फिलिस्तीनी मुद्दे पर आधारित निर्भर परिवर्त्य के रूप में अस्तित्व न रख कर एक स्वतंत्र परिवर्त्य के रूप में विकसित हो रही थी। अब भारत ने इज़रायल के साथ बहुआयामी गहन राजनीतिक–आर्थिक–सामरिक–तकनीकी सम्बन्धों के विकास और इज़रायल–फिलिस्तीनी शांति वार्ता और संघर्ष को एक दूसरे से जोड़कर देखना बंद किया। अब इज़रायल के सम्बन्धों के विकास के लिए स्वतंत्र–संप्रभु फिलिस्तीन राज्य की स्थापना एक पूर्व शर्त नहीं थी। भारत ने अब इज़रायल से मैत्रीपूर्ण संबंध विकास के साथ–साथ संप्रभु फिलिस्तीन राज्य के उदय के समर्थन की नीति अपनायी। अब भारत उक्त दोनों मुद्दों पर प्रगति का समर्थक है। अब भारत की विदेश नीति में इज़रायल और फिलिस्तीन मुद्दे पर समान व्यवहार की नीति अपनाने पर बल दिया गया।

भारत ने इज़रायल से सामरिक सहयोग, आतंक–निरोध, आर्थिक, कृषि, विज्ञान–तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में पारस्परिक लाभदायक दो–पक्षीय संबंध विकसित किए। इज़रायल ने भी जरूरत पड़ने पर भारत का समर्थन एवं मदद की। भारत–इज़रायल के बीच उत्तर–संबंध स्थापना काल में विभिन्न क्षेत्रों में गहन सहयोग की शुरुआत किए जाने के बावजूद दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों का प्रोफाइल लगभग अपवादस्वरूप निम्न ही बना रहा। साथ ही इज़रायल से संबंधो की स्थापना के बाद से भारत ने संयुक्त राष्ट्र और इसकी आनुषंगिक संस्थाओं में फिलिस्तीन के मुद्दे पर फिलिस्तीन प्राधिकरण के पक्ष में मतदान करने की नीति अपनायी जो आज तक जारी है। नवंबर 2012 को भारत ने सयुंक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को गैर–सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव का समर्थन किया। अपवादस्वरूप 1991 में भारत ने जिओनवाद को नस्लवाद बताने वाले 1975 के सयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को समाप्त करने के पक्ष में मत दिया

था और 2001 में डरबन सम्मेलन में भी भारत ने इज़रायल के पक्ष में रुख अपनाया।

लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा नीत एनडीए सरकार में भारत–इज़रायल संबंधो को नवीन ऊंचाई और उच्च प्रोफाइल देने की कोशिश की गयी। मई 1998 के परमाणु परीक्षण की इज़रायल ने आलोचना नहीं की। भारत पर तकनीकी निर्यात के प्रतिबंध के समय इज़रायल ने हथियारों का निर्यात न केवल जारी रखा बल्कि बढ़ाया भी। 1999 में कारगिल युद्ध के समय इजरायल द्वारा भारत की सैन्य मदद के पश्चात भारत–इजरायल सम्बन्धों में एक गुणात्मक परिवर्तन की शुरुआत हुई। कारगिल युद्ध के समय इज़रायल ने भारत को पाकिस्तानी पोजीशन की जानकारी संबंधी प्रतिमाएँ उपलब्ध कराई और अल्प समय में अति आवश्यक आर्टिरी शेल को उपलब्ध कराया। यहाँ से भारत–इजरायल रक्षा सहयोग को गति मिली। 2002 में पाकिस्तान के खिलाफ आपरेशन पराक्रम की योजना के समय इज़रायल ने भारत को विशेष विमान से सैन्य उपकरण उपलब्ध कराये थे। इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शेरॉन की सितंबर 2003 में भारत यात्रा के साथ दोनों देशों के बीच अब तक विद्यमान निम्न प्रोफाइल भारत–इज़रायल सम्बन्धों को उच्च प्रोफाइल का रूप देने की कोशिश की गयी। यह किसी भी इज़रायली प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा थी।

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्वार्टेट के रोड मेप के आधार पर इज़रायल–फिलिस्तीन शांति वार्ता का समर्थन सदैव ही किया है। परंपरागत रूप से भारत ने फिलिस्तीन राज्य की स्थापना को लेकर भी इसके उदय का समर्थन किया। भारत ने इज़रायल में फिलिस्तीनी आत्मघाती बम दस्तों एवं अन्य आतंक कृत्यों की आलोचना करना भी शुरू किया। भारत ने फिलिस्तीनी हिंसक उग्रवादी गतिविधियों की आलोचना शुरू की। 1 जून 2001 को तेल अवीव में हुए आत्मघाती हमले की आलोचना करते हुए भारत ने कहा कि "हिंसा के ऐसे कृत्य को किसी आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया

जा सकता।"[39] दिसंबर 2004 को सम्पन्न भारत–इजरायल सयुंक्त कार्य समूह की चौथी बैठक में दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी कृत्यों की आलोचना की।[40] विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक वक्तब्य में 25 जून 2006 को गाज़ा के निकट केरेम शलोम क्रासिंग पर इजरायली सैनिक के अपहरण की घटना की निंदा करते हुए विश्वास व्यक्त किया गया कि बंधक इजरायली सैनिक की रिहाई बढ़ते हुए तनाव को कम करने में मददगार होगी।[41] इसी प्रकार 12 जुलाई 2006 को लेबनान के मिलिटेंट द्वारा दो इज़रायली सैनिकों के अपहरण की भी भारत ने निंदा की।[42]

फिलिस्तीन और इज़रायल के आपसी संबंध और फिलिस्तीन और इज़रायल के बीच तनाव एवं संघर्ष के मुद्दे पर भारत की नीति में एक उतार–चढ़ाव दृष्टिगोचर होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा नीत एनडीए सरकार ने फिलिस्तीनियों के प्रति इज़रायली व्यवहार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में चिंता का रुख अपनाया लेकिन इज़रायल की आलोचना नहीं की। भारत ने उग्र फिलिस्तीनी तत्वों की हिंसक गतिविधि के साथ साथ इज़रायल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों के अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की। 24 मई 2001 को एक वक्तब्य में भारत ने इज़रायल और फिलिस्तीन पक्षों से "बिना शर्त समस्त हिंसक गतिविधियों को समाप्त करने, उकसावा रोकने और स्थिति को सामान्य करने की अपील की।"[43] अप्रैल 2002 के एक प्रेस वक्तब्य में फिलिस्तीनी शहर और कस्बों में इजरायली अतिक्रमण के तात्कालिक अंत के साथ साथ आतंक, हिंसा, उकसावा और भड़काव के चक्र के अंत पर बल दिया गया।[44] सितंबर 2002 के विदेश मंत्रालय के एक वक्तब्य में कहा गया कि "दो आत्मघाती बम हमलों और रमल्ला में राष्ट्रपति यासिर अराफात के परिसर के खिलाफ इज़राइली सेना के अतिक्रमण से सुरक्षा स्थितियों में गिरावट आई है।"[45] मार्च 2003 में इज़रायल और फिलिस्तीन क्षेत्र में हिंसा में बृद्धि के प्रति चिंता व्यक्त की गयी।[46]

कांग्रेस नीत यूपीए सरकार में भारत ने फिलिस्तीन राज्य के समर्थन के साथ–साथ इज़रायल–फिलिस्तीन शांति वार्ता का समर्थन किया गया,

इज़रायल के साथ बहुआयामी लाभदायक सहयोग को आगे बढ़ाया गया। इस दौरान कोई उच्च राजनीतिक यात्रा सम्पन्न नहीं हुई और भारत–इज़रायल सम्बन्धों का प्रोफाइल निम्न बना रहा। लेकिन फिलिस्तीन क्षेत्रों के प्रति इजरायली अतिक्रमण और व्यवहार के प्रति रुख में कदाचित परिवर्तन देखने को मिलता है। विदेश मंत्रालय के वक्तब्यों के तुलनात्मक अध्ययन से पता लगता है वर्ष 2004 के बाद इजरायल–फिलिस्तीनी संघर्ष के दौरान भारत ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायल की आक्रामकता की तो आलोचना की लेकिन गाज़ा से इजरायल पर होने वाले हमलों का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं किया। सरकार द्वारा 20 मई 2004 को एक वक्तब्य में गाज़ा में राफा फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में मकानो के ढहाने एवं इजरायली सेना द्वारा अतिशय बल के प्रयोग की निंदा की गयी और इज़रायली एक पक्षीय कार्रवाही को तत्काल रोकने की बात की गयी।[47] अक्तूबर 2004 में उत्तरी गाज़ा में हिंसा में बढ़ोत्तरी पर विदेश राज्य मंत्री ने कहा "हम उत्तरी गाज़ा में हिंसा की हालिया बृद्धि और इजरायली बलों द्वारा असमानुपातिक और बड़े पैमाने पर बल प्रयोग की निंदा करते है।"[48] जून 2006 को विदेश मंत्रालय द्वारा एक वक्तब्य में कहा गया कि भारत गाज़ा में इजरायली रक्षा बलों द्वारा बिना किसी उकसावे के द्वारा महिलाओं और बच्चों समेत निर्दोष नागरिकों के मारे जाने की निंदा करता है।[49] 2006 में इजरायल–लेबनान सीमा पर संघर्ष में भारत ने इज़रायल द्वारा लेबनान में अत्यधिक और असमानुपातिक बल के प्रयोग की निंदा की जिसमें बेरूत हवाई अड्डे समेत नागरिक आधारभूत संरचना को निशाना बनाया गया।[50] जनवरी 2009 के एक वक्तब्य में भारत सरकार ने इजरायली जमीनी एवं अन्य बलों द्वारा गाज़ा में जारी अतिक्रमण की निंदा की।[51] लेकिन 2012 में इज़रायल–फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान भारत ने अपने वक्तब्य से इज़रायल के संदर्भ में निंदा या आलोचना के रुख का विलोपन किया। गाज़ा में हिंसा पर मीडिया के प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गाज़ा के आसपास केन्द्रित इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा की तीव्र बृद्धि पर चिंता व्यक्त

की।[52] इस प्रकार वर्ष 2012 में यूपीए सरकार ने इज़रायल–फिलिस्तीन हिंसक संघर्ष के संबंध में एक नवीन रुख का प्रदर्शन किया।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि फिलिस्तीनियों के प्रति इज़रायली व्यवहार को लेकर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में कुछ उतार–चढ़ाव के प्रतिमान को छोड़कर क्रमिक रूप से नरमी दिखायी। एनडीए सरकार के काल में इज़रायल–फिलिस्तीन हिंसक संघर्ष में इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र का अतिक्रमण किए जाने संबंध में भारत ने चिंता व्यक्त की किन्तु इज़रायल की आलोचना नहीं की। बाद में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार काल में इज़रायल–फिलिस्तीनी संघर्ष में इज़रायली रक्षा बलों द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बल प्रयोग करने पर इज़रायल की आलोचना करने की नीति को अपनाया। लेकिन 2012 में इस नीति में भी परिवर्तन आया और फिलिस्तीनी–इज़रायल हिंसा और इज़रायल द्वारा फिलिस्तीन क्षेत्र का अतिक्रमण होने की स्थिति में इज़रायल की निंदा करने की नीति से बचा गया है।

फिलिस्तीन समस्या से संबन्धित एक अन्य महत्वपूर्ण किन्तु संवेदनशील मुद्दे यानि पूर्वी जेरूसलेम की स्थिति पर भारत की नीति में भी परिवर्तन परिलक्षित हुआ। शुरू से ही भारत की नीति इज़रायल–फिलिस्तीन विवाद के दो–राज्य समाधान के पक्ष में रही है और भारत ने स्वतंत्र एवं संप्रभु फिलिस्तीन राज्य के उदय और इज़रायल के साथ इसके शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का समर्थन किया है किन्तु सरकार के किसी भी औपचारिक वक्तव्य या कथन में जेरूसलेम के मुद्दे पर कोई विशिष्ट रुख नहीं अपनाया गया। हालांकि फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण ने सदैव ही पूर्वी जेरूसलेम को भावी फिलिस्तीन राज्य की राजधानी बताया था लेकिन भारत ने जेरूसलेम का उल्लेख किए बिना ही फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन किया था। सर्वप्रथम 1994 और पुनः अगस्त 2008 में भारत–इज़रायल संबंधो में राजनयिक संवाद के दौरान जेरूसलेम का मुद्दा उभरकर सामने आया था। 2009 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण प्रमुख

महमूद अब्बास की भारत यात्रा के दौरान तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सार्वजनिक रूप से पहली बार जेरूसलेम का जिक्र फिलिस्तीन राज्य और उसकी राजधानी पूर्वी जेरूसलेम के रूप में किया था। यह इज़रायल के लिए नकारात्मक कथन था। इस समय से भारत के फिलिस्तीन संबंधी वक्तब्य/कथन में पूर्वी जेरूसलेम का उल्लेख नियमित रूप से किया जाने लगा।[53]

मोदी सरकार और इज़रायल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए–2 सरकार में इज़रायल के प्रति भारत की नीति और रुख में विशिष्ट परिवर्तन का संकेत मिला है। मोदी सरकार ने कई कदमों के द्वारा स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वह भारत–इज़रायल सम्बन्धों एवं संपर्कों को एक नवीन उच्च प्रोफाइल देगी। दोनों देशों में राजनीतिक संपर्क बढ़ने और भारत–इजरायल संबंध का प्रोफाइल उच्च होने की संभावना अब बलबती हुई है। अब संभावना बढ़ गयी है कि दोनों देशों के संबंध में उच्च राजनीतिक संपर्क और संवाद को बढ़ाकर सार्वजनिक झिझक को समाप्त किया जा सकता है। इज़रायल के प्रति उच्च राजनीतिक स्तर पर सार्वजनिक झिझक को दूर किए जाने की नीति पर बल दिया जा रहा है। इसी क्रम में सितंबर 2014 के अंत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अमरीका में सयुंक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन के दौरान मुलाक़ात की थी।[54] इस समय इज़रायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत–इज़रायल सम्बन्धों में 'आसमान ही सीमा है।'[55] इज़रायल के अधिकारियों ने कहा कि यह मुलाक़ात दोनों देशों में "भावी सहयोग के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगी।"[56] प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार के गठन के बाद यथार्थवादी सामरिक समुदाय में व्यक्त की गयी संभावना के अनुरूप विदेश मंत्री द्वारा घोषणा की गयी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़रायल जाएंगे। हालांकि इस संबंध में किसी तिथि की घोषणा नहीं की गयी है जो कि दोनों पक्षों

की सुविधा और सहमति से तय की जाएंगी।[57] प्रधानमंत्री मोदी इज़रायल जाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होंगें। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन के प्रति भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं है। फिर भी यह एक नीतिगत बदलाव को अवश्य दर्शाता है क्योंकि अब तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इज़रायल यात्रा पर नहीं गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज़रायल यात्रा न केवल भारत–इजरायल सम्बन्धों में विकसित होते उच्च राजनीतिक प्रोफाइल को प्रतिबिम्बित करती है बल्कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच पूर्व से विकसित हो रहे बहुआयामी लाभदायक संबंधो में और भी अधिक गहनता और गुणात्मक परिवर्तन आने की प्रबल संभावना भी है। यह यात्रा भारत–इज़रायल में विकसित हो रहे करीबी संबंधो को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की हिचकिचाहट को समाप्त करते हुए दो–पक्षीय संबंधो को पर्दे के पीछे से निकालकर खुला सार्वजनिक रूप प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी की इज़रायल यात्रा को 'अवश्यंभावी निष्कर्ष' के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है।[58] प्रधानमंत्री मोदी की इज़रायल यात्रा के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज फिलिस्तीन, इज़रायल और जार्डन की यात्रा पर जाएंगी जो की प्रधानमंत्री की यात्रा की पूर्वपीठिका के रूप में होगा।

अब दोनों देशों के संबंधो में और अधिक गहनता आने की उम्मीद है। रक्षा एवं आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर तकनीकी क्षेत्र में गहन साझेदारी को और आगे बढ़ाया जाएगा। नवंबर 2014 के प्रथम सप्ताह में भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह की इज़रायल यात्रा और इज़रायल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेज़ की भारत यात्रा दोनों देशों में पारस्परिक सहयोग को नवीन क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की दिशा का संकेत देती हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की इज़रायल यात्रा के दौरान भारत को सीमा सुरक्षा, उड्डयन सुरक्षा, जल संचयन, साइबर सुरक्षा की तकनीक देने एवं 'मेक इन इंडिया' की भारतीय पहल के संदर्भ में उन्नत तकनीक के भारत में हस्तांतरण और विकास पर चर्चा की गयी है। यह दोनों देशों में विकसित होते गहन 'उच्च तकनीक संबंध' का सूचक है। दोनों देश

अब उच्च तकनीकी संबंध स्थापित करेगें। इज़रायल 'मेक इन इंडिया' में भाग लेगा। 'मेक इन इंडिया' में इज़रायल ने अपनी रुचि व्यक्त की है और वह भारत में तकनीक हस्तांतरण और विकास का इच्छुक है। भारत की अपेक्षा है कि इज़रायल 'मेक इन इंडिया' में भाग ले और तीसरे देश को सयुंक्त रूप से निर्मित उत्पाद का निर्यात किया जाय। फरवरी 2015 में इज़रायल के रक्षा मंत्री मोशे यालोन ने भारत सरकार के औपचारिक निमंत्रण पर 'ऐरो इंडिया शो' में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इज़रायल मोदी सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल का स्वागत करता है और इसमें सहभाग भी लेगा।[59] 1992 में दोनों देशों में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से यह इज़रायल के किसी भी रक्षा मंत्री की पहली भारत यात्रा थी। यह दोनों देशों में सार्वजनिक स्तर पर बढ़ते रक्षा सम्बन्धों का संकेत देती है। अब प्रतीत होता है कि भारत–इज़रायल रक्षा संबंध पर्दे के पीछे से आगे बढ़कर सार्वजनिक आकार ले रहे है। अब तक भारत की नीति इज़रायल से रक्षा सम्बन्धों को सतह के नीचे रखने की थी। लेकिन अब इसमें परिवर्तन आया है। इज़रायली रक्षा मंत्री को 'ऐरो इंडिया शो' में औपचारिक निमंत्रण देकर भारत ने इज़रायल से रक्षा संबंधो को सार्वजनिक स्वरूप देने की नीति पर अमल किया है।

रक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग से आगे जाकर इज़रायल से और कृषि तकनीकी–आर्थिक सम्बन्धों में भी करीबी बढ़ेगी। दोनों देशो में दो–पक्षीय व्यापार और निवेश भी बढ़ा है और दोनों देश मुक्त व्यापार समझौता की ओर आगे बढ़ रहे है ताकि आर्थिक सम्बन्धों को मजबूत किया जा सके। दोनों देशों के बीच पूर्व की भांति रक्षा क्षेत्र में भी संबंध आगे बढ़ रहे हैं। चीन से सीमा पर तनाव और पाकिस्तान द्वारा सीमा पर गोलाबारी के बीच अक्तूबर 2014 के अंत में भारत सरकार ने इज़रायल से 3200 करोड़ रुपये की एक डील में एक इज़रायली कंपनी 'रफायल डिफेंस एड्वान्स्ड सिस्टम' से 8356 स्पाइक एंटी–टेंक गाइडिड मिसाइल और 321 लॉंचर खरीदने का निर्णय किया है। 10 नवंबर 2014 को इज़रायल

में भारत–इज़रायल द्वारा सयुंक्त रूप से विकसित लंबी दूरी की सतह से वायु मिसाइल (एलआर–एसएएम) बराक–8 का सफल परीक्षण किया गया है। बराक–8 मिसाइल का सफल परीक्षण उन्नत हथियार सिस्टम को विकसित करने में दो–पक्षीय सहयोग में एक मील का पत्थर है।

भारत के 10 राज्यों में भारत–इज़रायल कृषि सहयोग परियोजनाएं 'सेंटर आफ एक्सीलेंस' की स्थापना के रूप में अपने क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 2015 तक इन 'सेंटर आफ एक्सिलेन्स' की संख्या बढ़ाकर 28 करने की योजना है। कृषि में सहयोग के लिए वर्तमान में चालू तीन वर्षीय कार्ययोजना को 2015 के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

भारत–इज़रायल सम्बन्धों में फिलिस्तीन का प्रश्न शुरू से ही एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। भारत फिलिस्तीन का समर्थक है लेकिन मोदी सरकार में कुछ नीतिगत परिवर्तन आने की संभावना है। जुलाई 2014 में शुरू हुए गाज़ा में इजरायल–हमास संघर्ष के दौरान इजरायल के प्रति विपक्ष के आलोचनात्मक रुख के बावजूद भारत सरकार ने संसद में इजरायल के खिलाफ किसी निंदा का प्रस्ताव पारित करने से इंकार किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि फिलिस्तीन और इजरायल के साथ भारत के संबंध पुरानी सरकारों की विरासत हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत की नीति को स्पष्ट करते हुए जुलाई 2014 में कहा कि फिलिस्तीन के प्रति भारत की नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। गाज़ा संघर्ष में किसी का पक्ष लेने से इंकार करते हुए सरकार ने कहा कि इज़रायल और फिलिस्तीन को शांति वार्ता करना चाहिए। भारत की नीति इज़रायल के साथ अच्छे सम्बन्धों को बनाए रखते हुए फिलिस्तीन मुद्दे का पूरा समर्थन करना है।[60] भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के उस प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया जिसमें गाज़ा पर इज़रायल की सैन्य कार्रवाही की जांच करने की बात की गयी थी।[61] यह मत भी प्रतीकात्मक अधिक ही था और फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की परंपरागत नीति के समर्थन में अधिक था।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अमरीका यात्रा में न्यूयोर्क में इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतान्याहु से मुलाकात की लेकिन फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास से मुलाक़ात नहीं की।[62] संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी अतीत वर्षों की फिलिस्तीनी नीति से प्रस्थान दर्शाता है क्योंकि अतीत में भारतीय भाषणों में लगभग नियमित रूप से 'फिलिस्तीन संघर्ष' और फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में पूर्वी जेरूसलेम का संदर्भ दिया जाता था। सार्वजनिक वक्तब्य में भारतीय बदलाव आने के बाद 2013 में भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भावी स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में पूर्वी जेरूसलेम पर फिलिस्तीनी दावे का संदर्भ दिया था।[63] लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सयुंक्त राष्ट्र भाषण में फिलिस्तीनी मुद्दे का कोई जिक्र नहीं किया।[64] यह भारत की फिलिस्तीनी नीति पर सक्रियता में परिवर्तन का संकेत करता है। यह पुरानी प्रो–एक्टिव फिलिस्तीन नीति से कदाचित विचलन को दर्शाता है।

सयुंक्त राष्ट्र में इज़रायल–फिलिस्तीन संघर्ष के मुद्दे पर भारत की मतदान नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देखने को मिला हालांकि सरकार ने किसी नीतिगत परिवर्तन से इंकार किया।[65] 3 जुलाई 2015 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में जुलाई–अगस्त 2014 में घटित गाज़ा युद्ध के संबंध में सयुंक्त राष्ट्र जांच आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार करने के लिए होने वाले मतदान में भारत अनुपस्थित रहा। इस मतदान के तत्काल बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तब्य में कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे पर समर्थन करने की भारत की पुरानी नीति में कोई परिवर्तन नही आया है। इस मतदान में अनुपस्थित रहने की नीति के पक्ष में विदेश मंत्रालय ने तर्क दिया कि जांच प्रतिवेदन में इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में ले जाने का प्रत्यक्ष संदर्भ होने के कारण भारत ने अनुपस्थिति के विकल्प का चयन किया क्योंकि भारत इस न्यायालय को मान्यता नहीं देता है। अतीत में भी जब मानव अधिकार परिषद प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का

प्रत्यक्ष संदर्भ आया है जैसा कि सीरिया और उत्तरी कोरिया के मामले में हुआ था तो भारत ने अनुपस्थित रहने की नीति का ही अनुसरण किया था।[66] उल्लेखनीय है कि 22 दिसंबर 2014 के द हिन्दू समाचार पत्र के हवाले से यह खबर आयी थी कि अब भारत सयुंक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन मुद्दे पर अपनी मतदान नीति एवं प्रतिमान में परिवर्तन कर फिलिस्तीन को समर्थन बंद कर सकता है।[67] इस मतदान से संकेत मिलता है कि अब मोदी सरकार ने सयुंक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन मुद्दे के पक्ष में मतदान की करने की भारत की परंपरागत नीति के स्थान पर अनुपस्थित रहने की नीति को अपनाया है। यह भारत की फिलिस्तीन मुद्दे पर मतदान की नीति में मुलभूत परिवर्तन को प्रतिबिम्बित करता है। स्मरणीय है कि इज़रायल से रक्षा आदि क्षेत्रों में गहन संबंध बनाने के बाद यूपीए सरकार ने ईरान के प्रति नीति में तनिक बदलाव लाया था लेकिन फिलिस्तीन पर मतदान की नीति यथावत बनी रही थी। फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की मतदान नीति भारत–इज़रायल सम्बन्धों में एक अड़चन/रुकावट बनी थी। इज़रायल के राजनीतिक वर्ग में शिकायत थी कि करीबी संबंध बनाने के बाद भी भारत के फिलिस्तीनी रुख में परिवर्तन देखने को नहीं मिला था। एक वरिष्ठ इज़रायली इंटरलोक्यूटर ने इजरायल यात्रा पर गए भारतीय विदेश मंत्री से कुछ समय पूर्व कहा था कि नई दिल्ली ने तेल अवीव को एक 'मिस्ट्रेस' की तरह समझा है यानि भारत ने दो–पक्षीय संबंधो को सार्वजनिक गेज़ से अलग रखा है।[68] भारत की मतदान नीति में संशोधन जहां इज़रायल के लिए एक सुखद खबर जरूर है लेकिन पश्चिम एशिया के राज्यों एवं फिलिस्तीनी प्राधिकरण में भारत की विदेश नीति के भावी मार्ग को लेकर शंका जरूर उठेगी।

इज़रायल ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में गाज़ा युद्ध पर सम्पन्न मतदान में भारत के अनुपस्थित रहने की प्रशंसा की और कहा कि इससे दोनों देशों के सम्बन्धों में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। इज़राइली विदेश मंत्रालय के उप–महानिदेशक मार्क सोफ़र ने कहा कि मोदी सरकार

के गठन के बाद से दोनों देशों के सम्बन्धों में एक गुणात्मक परिवर्तन आया है और दोनों देशों के बीच संबंध अब बिना किसी अवरोध के 'पूर्णतः सामान्य संबंध' में रूपांतरित हुए हैं। सोफ़र दोनों देशों के संबंधो में बेहतरी का श्रेय काफी हद तक प्रधानमंत्री बिनयामिन नेतान्याहु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं।[69] मीडिया सूत्रों का यह भी कहना है कि इस मतदान की पूर्व संध्या पर इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतान्याहु ने भारत के प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी से फोन पर वार्ता की थी।[70]

वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन प्राधिकरण ने यात्रा पर गए विदेश मंत्रालय के सचिव अनिल वाधवा से भारत द्वारा इस मतदान में अनुपस्थित रहने के लिए भारत से सफाई मांगी है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत ने भारत द्वारा मतदान में अनुपस्थिति के लिए दिये गए तर्क को संतोषजनक नहीं माना है किन्तु आशा व्यक्त की है की यह एक लघु अपवाद है और भारत की नीति में परिवर्तन नहीं है।[71]

अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के दौरान भारत के राहत राजनय ने भारत–इज़रायल संबंधो को भावनात्मक आयाम प्रदान किया। नेपाल भूकंप में भारत ने अपने व्यापक बचाव एवं राहत कार्य के समय इस देश में भूकंप में फंसे इज़रायल के नागरिकों को भी बचाया। इज़रायल के प्रधानमंत्री बिनयामिन नेतान्याहु ने भारत को इस बात के लिए धन्यवाद दिया। जहां यह भारत की कूटनीति के मानवतावादी पहलू को प्रतिबिम्बित करता है वहीं इसने भारत–इज़रायल सम्बन्धों को भावनात्मक जुड़ाव का आयाम प्रदान किया।

इस प्रकार स्पष्ट होता है की मोदी सरकार ने भारत–इज़रायल सम्बंधो के अग्रगामी बहुआयामी विकास को काफी गंभीरता से लिया है और अब यह इज़रायल से दो–पक्षीय संबंधी को एक नवीन आयाम और गति देने की इच्छुक प्रतीत होती है। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की सामरिक गणना में इज़रायल का महत्व बहुत बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। भारत की

आतंक–निरोध की नीति में भी इज़रायल को एक बड़े समर्थक के रूप में देखा जा रहा है विशेषकर खुफिया सूचना संग्रहण और आतंक–रोधी तकनीक की प्राप्ति के क्षेत्र में। केनेथ वाल्स के संरचनात्मक यथार्थवाद की धारणा के अनुरूप मोदी सरकार का भारत की क्षमता निर्माण पर अत्यधिक बल है। इस क्षमता निर्माण में तकनीक के महत्व की भूमिका पर मोदी सरकार ने काफी बल दिया है। रक्षा, कृषि, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, जल प्रबंधन, आतंकवाद–निरोध जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इज़रायल की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ लेने के लिए मोदी सरकार इज़रायल से गहन और उच्चीकृत संबंधो का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध प्रतीत होती है। भारत के लिए इज़रायल एक उच्च तकनीक का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभर रहा है। इस तकनीक को प्राप्त करने के लिए मोदी सरकार इज़रायल के प्रति भारत की झिझकता के रुझान को बदलने के लिए संकल्पित प्रतीत होती है। भारत के विकास की कहानी को 'स्टेट आफ द आर्ट' और 'कटिंग एज़ तकनीक' के समर्थन की आवश्यकता है और इज़रायल इस समर्थन को देने के लिए तैयार प्रतीत होता है। मोदी सरकार का इज़रायल के बारे में यह परिवर्तित सोच और नजरिया दोनों देशों के सम्बन्धों को नवीन आयाम और ऊंचाई दे सकने की संभावना समेटे हुए प्रतीत होता है।

बहुआयामी सम्बन्ध

भारत–इज़रायल ने विभिन्न क्षेत्रों में करीबी संबंध विकसित किए हैं। दोनों देशों के संबंध पारस्परिक जरूरत के आधार पर विकसित हो रहे हैं। दोनों को कई मामलों में एक दूसरे की जरूरत है। भारत के लिए इज़रायल उन्नत तकनीक की प्राप्ति के एक बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। रक्षा, कृषि, जल संचयन, उड्डयन सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, आतंक–निरोध, आंतरिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में भारत इज़रायल की तकनीक को प्राप्त कर रहा है। मेक इन इंडिया में इज़रायल ने अपनी रुचि व्यक्त की है और वह भारत में तकनीक हस्तांतरण और विकास का इच्छुक है। दोनों देशो में दो–पक्षीय व्यापार और निवेश भी बढ़ा है और दोनों देश मुक्त

व्यापार समझौता की ओर आगे बढ़ रहे है ताकि आर्थिक सम्बन्धों को मजबूत किया जा सके। इज़रायल के लिए भारत का भी काफी महत्व है। इज़रायली रक्षा एवं कृषि तकनीक व उत्पादों के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। भारत के साथ राजनयिक संबंध से इज़रायल की वैधता बढ़ी है।

भारत अपनी रक्षा जरूरतों का 70 प्रतिशत विदेशी स्रोतों के क्रय करता है।[72] सैन्य–सुरक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने सहयोग को काफी बढ़ाया है। भारत बड़ी मात्रा में इज़रायल से हथियारों का आयात कर रहा है। 2012 में इज़रायल का रक्षा निर्यात सात बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें भारत का अंश लगभग एक बिलियन अमरीकी डालर से अधिक था।[73] भारत को हथियारों की आपूर्ति के मामले में रूस के बाद इज़रायल का दूसरा स्थान है।[74] चीन से सीमा पर तनाव और पाकिस्तान द्वारा सीमा पर गोलाबारी के बीच अक्तूबर 2014 के अंत में भारत सरकार ने इज़रायल से 3200 करोड़ रुपये की एक डील में एक इज़रायली कंपनी 'रफायल डिफेंस एड्वान्स्ड सिस्टम' से 8356 स्पाइक एंटी–टेंक गाइडिड मिसाइल और 321 लाँचर खरीदने का निर्णय किया है।[75] अक्तूबर 2014 की गार्जियन अखवार की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने सोवियत युगीन सैन्य उपकरणों को अपग्रेड करने में 250 बिलियन डालर निवेश करने की योजना बनाई है।[76] 10 नवंबर 2014 को इज़रायल में भारत–इज़रायल द्वारा सयुंक्त रूप से विकसित लंबी दूरी की सतह से वायु मिसाइल (एलआर–एसएएम) बराक–8 का सफल परीक्षण किया गया है।[77] यह मिसाइल 'इज़रायली ऐरोस्पेस इंडस्ट्री' और 'रक्षा शोध एवं विकास संगठन' (डीआरडीओ) द्वारा सयुंक्त रूप से विकसित की गयी है। डीआरडीओ मुखिया अविनाश चंदर और भारतीय सेना के अधिकारी मिसाइल परीक्षण के समय इज़रायल में थे। चंदर के अनुसार बराक–8 मिसाइल का सफल परीक्षण उन्नत हथियार सिस्टम को विकसित करने में दो–पक्षीय सहयोग में एक मील का पत्थर है।[78] इस मिसाइल को सयुंक्त रूप से विकसित करने के लिए जनवरी 2007 में समझौता

किया गया था।[79] भारत–इज़रायल रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ऑफसेट मुद्दे के प्रबंधन से संबन्धित है जिसके क्रियान्वयन पर ध्यान देना भी जरूरी है। ऑफसेट क्लाज़ क्रेता राज्य द्वारा रक्षा सौदों में प्रतिपूर्ति पाने का एक उपाय है ताकि वह अपने देश में स्वदेशी सैन्य–औद्योगिक संकुल का विकास कर सके। भारत सरकार द्वारा 2005 में घोषित रक्षा प्रोक्योरमेंट नीति में पहली बार ऑफसेट क्लाज़ का प्रावधान किया गया था। इसके अनुसार 300 करोड़ से अधिक का रक्षा सौदा होने की स्थिति में विक्रेता राज्य या कंपनी द्वारा भारत में सौदे की राशि के 30 प्रतिशत का निवेश रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष या सयुंक्त उपक्रम के माध्यम से किया जाएगा। आज भारत इज़रायल से काफी रक्षा हथियार क्रय कर रहा है और 2012 में यह आंकड़ा एक बिलियन डालर का था। 2005 के बाद अब तक हुए कुल रक्षा सौदों की मूल्य गणना कर इसके 30 प्रतिशत ऑफसेट का आकलन कर इज़रायल से ऑफसेट क्लाज़ के क्रियान्वयन पर तत्परता प्रदर्शित करना जरूरी है। इज़रायल के संदर्भ में भारत का ऑफसेट कई मिलियन डालर होगा। इस ऑफसेट मुद्दे पर ध्यान देकर रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है।

1992 में राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के बाद से दोनों देशों के बीच दो–पक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध में काफी तीव्र प्रगति हुई है।[80] दोनों देशों में दो–पक्षीय व्यापार 2012–13 में छ्ह बिलियन डालर था।[81] भारत–इज़रायल मुक्त व्यापार समझौता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। भारत में इज़रायल के तत्कालीन राजदूत अलोन उश्पिज के अनुसार भारत–इज़रायल मुक्त व्यापार समझौता होने से दोनों देशों देशों के व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा और व्यापार सम्बन्धों में 'सामरिक बदलाव' आएगा और यह 'सामरिक गेम चेंजर' साबित होगा।[82]

कृषि क्षेत्र में दोनों देशों में काफी सहयोग बढ़ा है। इज़रायल की कृषि तकनीक एवं ज्ञान काफी विकसित है और भारत इससे लाभान्वित हो रहा है। इस क्षेत्र में सहयोग के अंतर्गत "ज्ञान और तकनीक की साझेदारी,

विभिन्न कृषि क्षेत्रों में भारत भर में 'सेंटर आफ एक्सीलेंस' की स्थापना, विशेषज्ञों और किसानों की विनिमय यात्राएं और भारतीय कृषि शोध छात्रों को इज़रायल में स्कालरशिप देना सम्मिलित हैं।"[83] इस सहयोग का उद्देश्य इज़रायल की अद्यतन कृषि व्यवहार और तकनीक का भारत में क्रियान्वयन और समावेशन है। 2008 के कृषि सहयोग समझौते और 2011 की तीन वर्षीय कार्ययोजना (2012–15) के अंतर्गत देश के 10 राज्यों में भारत–इज़रायल कृषि सहयोग परियोजनाएं 'सेंटर आफ एक्सीलेंस' की स्थापना के रूप में अपने क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। हरियाणा में क्रमश सब्जी और फलों के लिए करमाल और सिरसा में दो 'सेंटर आफ एक्सीलेंस' पूर्ण रूप से चालू हो चुके हैं। 2015 तक इन 'सेंटर आफ एक्सिलेन्स' की संख्या बढ़ाकर 28 करने की योजना है।[84] इन केन्द्रों में इजरायल के कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को उत्पादन और लाभ बढ़ाने के लिए ग्रीन हाउस, पोली हाउस और कैनोपी जैसी 'उत्पादक कृषि' का प्रशिक्षण दिया जाता है एवं विभिन्न कृषि तकनीकों यथा वर्तिकल फ़ार्मिंग, ड्रिप सिचाई, मृदा सोलराइजेसन आदि का प्रदर्शन किया जाता है। इन केन्द्रों के पीछे "मूल विचार भारत के विभिन्न राज्यों में किसानों को व्यावहारिक शोध और तकनीक का हस्तांतरण करना है।"[85] कृषि में सहयोग के लिए वर्तमान में चालू तीन वर्षीय कार्ययोजना को 2015 के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।[86] इन केन्द्रों की स्थापना के पीछे सहयोग का उद्देश्य सयुंक्त भारत–इजरायली कृषि शोध एवं विकास के लिए मंच उपलब्ध कराना है।[87] उक्त क्षेत्रों के अलावा दोनों देश विज्ञान एवं तकनीक, अन्तरिक्ष विज्ञान, आतंकवाद निरोध, आदि क्षेत्रों में भी सहयोग कर रहे हैं। 2008 में भारत ने इज़रायल की एक 'टेक–सार' राडार खुफिया उपग्रह को प्रक्षेपित किया था।

निष्कर्ष

इस प्रकार भारत की इज़रायल नीति 1947 में जिओनवाद एवं इज़रायल के उदय का विरोध करने और 1950 में इज़रायल को मान्यता देने

और अति सीमित राजनयिक सम्बन्धों के एक ध्रुव से चलकर 1992 में इज़रायल से राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना करने और बहुपक्षीय गहन संबंधो के विकास के दूसरे ध्रुव तक पहुँचती है। दोनों ही समय यानि 1950 और 1992 में इज़रायल के प्रति अपनायी गयी नीति और राजनयिक व्यवहार के पक्ष में तर्क और कारण प्रस्तुत किए गए। परिवेश और नीति में बदलाव अवश्य आया लेकिन दोनों ही कालखंड में इनके मूल में मुख्य रूप से तीन सामरिक तत्व संचालक तत्व की भूमिका में थे। तब और अब दोनों समय भारत की इज़रायल नीति में भारत की उत्तरजीविता और सुरक्षा चिंतायें, सामरिक स्वायत्ता का प्रश्न और आर्थिक विकास का कारक अंतर्वलित था।[88] लेकिन प्रश्न है कि अरब समर्थन की एकतरफा नीति से भारत के उक्त सामरिक लक्ष्यों की पूर्ति कहाँ तक हो सकी। इस संबंध में निकोलस ब्लेरल का कहना है कि "भारत की पश्चिम एशिया नीति से भारत की ऊर्जा दुविधा को कुछ राहत अवश्य मिली लेकिन यह इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक स्वायत्ता को सुनिश्चित करने में असफल रही जब कि भारतीय नेतृत्व लगातार बिना शर्त अस्सी के दशक के अंत तक अरब पहल का समर्थन करता रहा।"[89]

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या सातवें एवं आठवें दशक के मध्य तक भारत की इज़रायल नीति की समीक्षा, मूल्यांकन और तत्संबंधी व्यावहारिक राजनयिक परिवर्तन किए जाने की जरूरत थी? राजनीतिक गलियारों में यह विमर्श शुरू हो गया था लेकिन इसकी झलक नीतिगत परिवर्तन में प्रतिविम्बित नहीं हुई थी। इस समय देश में इन्दिरा कांग्रेस और जनता पार्टी सत्ता में थी। पश्चिम एशिया नीति में परिवर्तन का प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि भारत की एकतरफा अरब समर्थन की नीति के बाद भी इसे चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों एवं कश्मीर मुद्दे पर अपेक्षित अरब समर्थन नहीं मिला था। इस समय तक लगभग स्पष्ट हो चुका था कि एकतरफा अरब समर्थन की नीति से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के संबंध में अरब पक्ष से लगभग मोहभंग की स्थिति बनती नजर आ रही थी। लेकिन

कोई नीतिगत परिवर्तन नहीं आया। क्यो? इस काल में भी एकतरफा अरब समर्थक नीति के पक्ष में क्या वही परंपरागत कारण विद्यमान थे यथा ऊर्जा सुरक्षा, अरब समर्थक परंपरागत राजनीतिक विचारधारा, अरब राज्यों को पाकिस्तान से दूर रखना, देश की जनांककीय संरचना आदि। क्या कोई ग्लोबल कारण भी भारत की इज़रायल नीति को प्रभावित कर रहे थे? क्या इस काल में भारत की एकतरफा अरब समर्थन की नीति में एक नवीन नीति निर्धारक तत्व के रूप में सोवियत कारक की भी कोई भूमिका थी?

यह सही है कि सोवियत संघ ने इज़रायल के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।[90] सोवियत संघ ने सयुंक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इज़रायल को विधिक मान्यता देने वाला पहला देश सोवियत संघ था। प्रथम अरब–इज़रायल युद्ध में भी सोवियत नीति लगभग इज़रायल के पक्ष में झुकी हुई थी। लेकिन परवर्ती काल में सोवियत नीति इज़रायल विरोधी और अरब समर्थन में झुकती चली गयी थी और 1967 के अरब–इज़रायल युद्ध के बाद सोवियत संघ ने इज़रायल से राजनयिक संबंध समाप्त कर लिए थे। अरब–इज़रायल संघर्ष और युद्धों में सोवियत संघ ने अरब राज्यों को नैतिक, राजनीतिक और सैन्य समर्थन किया था।[91] इज़रायल और मिस्र के बीच 1978 के केंप डेविड समझौते की भी सोवियत संघ ने कटु आलोचना की थी। इस प्रकार सत्तर और अस्सी के दशक में भी सोवियत संघ की एकतरफा अरब समर्थन की नीति जारी रखी थी। इसी समय इन्दिरा गांधी की सरकार ने सोवियत संघ की तरफ कदम बढ़ते हुए भारत–सोवियत मैत्री संधि को स्वीकार किया था। सोवियत संघ ने 1971 में भारत–पाकिस्तान युद्ध में खुलकर भारत का समर्थन किया था। अब सोवियत संघ भारत का एक बड़ा हथियार निर्यातक बन कर उभरा था। भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए कमोवेश सोवियत समर्थन का सहारा ले रहा था।

इस कालखंड में सोवियत संघ की पश्चिम एशिया नीति का भारत की एकतरफा अरब समर्थन नीति से कोई संबंध है? इस कालखंड में भारत–सोवियत मैत्री अपने शिखर पर थी और सोवियत संघ की नीति इज़रायल विरोध और अरब समर्थन की थी। भारत की सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में अरब राज्यों से मोहभंग के बाद भी इज़रायल नीति में संशोधन नहीं किया गया तो कहीं इसका कारण सोवियत कारक तो नहीं था? मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने खालिस गुटनिरपेक्षता की बात की और भारत की इज़रायल नीति का मूल्यांकन करने की कोशिश की लेकिन चाहते हुए भी भारत की इज़रायल नीति में वास्तविक संशोधन एवं परिवर्तन नहीं कर सकी थी। भारत की पश्चिम एशिया और इज़रायल नीति में सोवियत कारक पर नवीन शोध और गंभीर अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। शोध अध्ययनों में इस परिकल्पना पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है कि भारत की सुरक्षा चिंता के संबंध में अरब राज्यों से मोहभंग के दौर में सोवियत संघ की ओर भारत के बढ़ते हुए कदमों ने भारत की इज़रायल नीति में संशोधन करने या न करने की नीति को कहाँ तक प्रभावित किया था? सत्तर और अस्सी के दशक में भारत की इज़रायल नीति का पुनर्मूल्यांकन और तत्संबंधी संशोधन का स्थगन कहीं सोवियत प्रभाव के कारण तो नहीं किया गया? शायद अभी ऐसे कोई दस्तावेज़ या आनुभविक आधार उपलब्ध नहीं है जिससे उक्त तार्किक प्रतिज्ञप्ति या परिकल्पना को सत्य या असत्य घोषित किया जा सके। भविष्य में सार्वजनिक होने वाले दस्तावेज़ इस कालखंड में भारत की इज़रायल नीति में सोवियत कारक के होने या न होने की पुष्टि कर सकेंगे इसकी एक संभावना प्रतीत होती है।

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत की इज़रायल नीति में मूल्यांकन और संशोधन के विमर्श पर ध्यान देते हुए इज़रायल से संपर्क बढ़ाने की दिशा में कुछ राजनयिक कदम उठाए थे लेकिन 1992 में ही तत्संबंधी नीति परिवर्तन का निर्णय लिया जा सका था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी

द्वारा इज़रायल नीति का मूल्यांकन और संशोधन करने की शुरुआत की गयी थी। इसी समय सोवियत संघ में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोब ने पेरेस्त्रोइका और ग्लास्नोस्त की नीति अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधो के वि–वैचारिकीकरण और कामन यूरोपीय होम की बात की थी। गोर्वाचोब ने सोवियत संघ की पश्चिम एशिया नीति में भी संशोधन करते हुए अरब–इज़रायल संघर्ष के सैन्य समाधान की बजाय राजनीतिक समाधान की बात की थी तथा इज़रायल के प्रति भी नीति परिवर्तन के संकेत देना शुरू किए थे।[92] राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत की इज़रायल नीति में संशोधन का प्रयास और और गोर्वाचोब की उपरोक्त उदार नीति का एक ही कालखंड में एक साथ घटित होना क्या एक संयोग मात्र था? इस बात पर आनुभविक शोध किए जाने की जरूरत है कि क्या भारत की इज़रायल नीति में स्थगन और परिवर्तन में सोवियत कारक की कोई भूमिका थी?

जहां तक अमरीकी कारक का प्रश्न है तो निश्चित रूप से भारत की इज़रायल नीति में नौवें दशक में इस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमरीका ने 1948 में इज़रायल के उदय के समय से ही भारत से इज़रायल नीति में समायोजन की अपेक्षा की थी लेकिन तब इस अमरीकी कारक की उपेक्षा की गयी थी। लेकिन 1992 में इज़रायल से संबंध सामान्यीकरण की नीति में अमरीकी कारक काफी महत्वपूर्ण बनकर उभरा था। भारत की नई आर्थिक नीति को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका के समर्थन की जरूरत थी और अमरीका से करीबी संबंध के लिए इज़रायल से सम्बन्धों का सामान्यीकरण पूर्व शर्त थी।[93] 1992 में राजनयिक संबंधो की स्थापना के बाद से भारत–इज़रायल के बीच संबंध लगातार सुगढ़ हुए हैं। पूर्व में दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्धों के अभाव और अरब–फिलिस्तीन समर्थक नीति के अनुसरण करने के बावजूद भारत ने एक राज्य के रूप में इज़रायल के अस्तित्व को सदैव स्वीकार किया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने जिओनवाद का समर्थन भले ही

न किया हो लेकिन इन दोनों की एक कौम के रूप में सदियों से भेदभाव और अत्याचार का दंश झेलने वाले यहूदियों के साथ पूर्ण सहानभूति थी। इतिहास के किसी भी काल में भारत में यहूदी समुदाय के साथ कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। भारत में काफी समय से यहूदी निवास कर रहे थे। विश्व में संभवतः भारत ही एकमात्र देश था जहां यहूदियों का कभी भी विरोध नहीं किया गया और न ही एंटि–सेमेटिक गतिविधियां देखी गयी। भारत मे 'बनी इजरायली' काफी संख्या में मौजूद हैं। भारत के उत्तर–पूर्वी राज्य में एक समुदाय को मेनशीम यहूदियों के रूप में इज़रायल ने स्वीकार किया है।

1992 के पूर्व भी भारत–इज़रायल के बीच किसी न किसी रूप में राजनीतिक संपर्क, संवाद, आशाएँ और अपेक्षाएँ बनी रही। भारत की अरब समर्थन की नीति के बावजूद इज़रायल ने भारत को अपने पक्ष में करने के प्रयासों का त्याग नहीं किया। इज़रायल के प्रथम प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन का मानना था कि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के स्थगन का कार्य 'रणनीतिपरक हैं न की सैद्धान्तिक।'[94] गुरियन को आशा थी कि यह 'अल्पकालिक' ही होगा। नेहरू को संबोधित करते हुए गुरियन ने कहा कि "कई बार उन्होने(नेहरू) भारत यात्रा पर गए हमारे प्रतिनिधियों से वादा किया कि वह दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना करेंगे।"[95] गुरियन ने नेहरू से अपेक्षा किया कि अपने उक्त वादे को पूरा करते हुए इज़रायल से राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की जाय। भारत से राजनयिक संबंधो की स्थापना की आशा में इज़रायल ने जब भी मौका आया भारत की मदद की।[96] भारत के अपने पड़ोसियों के साथ हुए तमाम युद्धों के दौरान इज़रायल ने भारत को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। 1962 के भारत–चीन युद्ध में नेहरू ने डेविड बेन गुरियन को मदद के लिए कहा और इज़रायल ने भारत को सैन्य उपकरण दिये थे। 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में इज़रायल ने भारत को मोर्टार की आपूर्ति की थी।[97]

1992 में राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के पश्चात भारत–इज़रायल सम्बन्धों का बहुआयामी विकास त्वरित गति से हुआ है। परंपरागत रूप से भारत की पश्चिम एशिया नीति में अरब और फिलिस्तीन का समर्थन किया गया था और इज़रायल से राजनयिक दूरी बनाए रखी गयी थी। लेकिन शीतयुद्धोत्तर विश्व में भारत की इज़रायल नीति में बदलाव आया और इज़रायल से राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के साथ बहुआयामी साझेदारी–परक सम्बन्धों का विकास हुआ। लेकिन भारत–इज़रायल सम्बन्धों में गहनता के विकास के बावजूद संभवतः जानबूझकर संबंध निम्न प्रोफाइल के बने रहे और ध्यान आकर्षित करने वाली परस्पर उच्चस्तरीय यात्राओं की संख्या अधिक नहीं रही। 1996 में इज़रायल के राष्ट्रपति एजर वाइज़मेन और 2003 में इज़रायल के प्रधानमंत्री एरियल शेरॉन ने भारत यात्रा की थी। 2000 में भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने इज़रायल की यात्रा की थी। इसके बाद अब तक भारत के कई मंत्री, मुख्य मंत्री, इज़रायल की यात्रा कर चुके हैं। अब तक भारत के राज्य या शासन प्रमुख द्वारा इज़रायल की यात्रा नहीं की गयी है। लेकिन अब लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत–इज़रायल सम्बन्धों को नया उच्च प्रोफाइल देगी। अब संभावना है कि दोनों देशों के संबंध में उच्च राजनीतिक संपर्क बढ़ेगा और सार्वजनिक झिझक को समाप्त किया जाएगा और तकनीकी क्षेत्र में गहन साझेदारी को और आगे बढ़ाया जाएगा। वर्ष 2003 के बाद सितंबर 2014 में दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने अमरीका में मुलाक़ात की। नवंबर 2014 में भारत के गृह मंत्री ने इज़रायल यात्रा की तथा इज़रायल के पूर्व राष्ट्रपति ने भारत यात्रा की।

आतंक–निरोध के मुद्दे पर भारत और इज़रायल में हितों की पारस्परिकता उभरी है। दोनों ही देश के भीतर और बाहर से प्रायोजित आतंक के शिकार हैं और आतंक–निरोध पर सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन आतंकवाद के स्रोत के बारे में दोनों का रुख अलग–अलग है। भारत का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और यह भारत में

आतंक का निर्यात कर रहा है। इज़रायल के अनुसार ईरान आतंक का जनक है।

भारत–इज़रायल सम्बन्धों में ईरान, पाकिस्तान और चीन जैसे बाहरी असहज तत्व भी मौजूद हैं। भारत के ईरान के साथ करीबी संबंध, इज़रायल के चीन के साथ करीबी संबंध और इज़रायल द्वारा पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति की कथित खबरें तनिक असहज करतीं हैं लेकिन प्रतीत होता है दोनों देशों ने आपसी सम्बन्धों के विकास पर किसी अन्य बाहरी तत्व के प्रभाव को आने से नकारा है और राजनीतिक परिपक्वता का प्रदर्शन किया है। चीन एशिया में इज़रायल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इज़रायल–चीन के बीच सालाना व्यापार 10 बिलियन अमरीकी डालर है जब कि भारत–इज़रायल के बीच सालाना व्यापार लगभग 5 बिलियन अमरीकी डालर है। भारत को आश्वस्त करते हुए इज़रायल ने कहा है वह चीन के साथ हथियार व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। इसके अलावा अमरीका ने चीन को हथियार या रक्षा तकनीक कि आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चीन से बढ़ते आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्धों के बावजूद इज़रायल चीन को एक सामरिक साझेदार के रूप में नहीं देखता है। इज़रायल के अधिकारियों के अनुसार भारत के साथ सम्बन्धों में सामरिक घटक को कमज़ोर करते हुए चीन से संबंध बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है।[98] इस दृष्टि से चीन को इज़रायल का व्यापारिक साझेदार माना गया है जब कि भारत को इज़रायल का सामरिक साझेदार माना गया है।

ईरान कारक को भारत–इज़रायल सम्बन्धों के विकास में एक कमजोर कड़ी माना गया है। इज़रायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का कटु आलोचक है और इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है।[99] इज़रायल की अपेक्षा है भारत ईरान के साथ अपने सम्बन्धों को सीमित करे। इज़रायल के राष्ट्रपति शिमोन पेरेज ने ईरान को विश्व शांति और अन्य देशों के अस्तित्व के लिए खतरा मानते हुए कहा कि पश्चिम एशिया

क्षेत्र में 'बलात हेजेमोन' बनने के ईरान के 'आक्रामक प्रयत्नों' के प्रति भारत तटस्थ नहीं रह सकता।[100] भारत को ईरान से तेल आयात की आवश्यकता है। हालांकि भारत ने ईरान पर अमरीकी प्रतिबंधों के बाद से ईरान से तेल का आयात कम किया है। ऊर्जा सुरक्षा नीति के तहत भारत ने नए ऊर्जा स्रोतों की तलाश जारी रखी है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईरान से सहयोग और तेल आयात करने का तात्पर्य यह नहीं है वह ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करता है।[101] अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरोध में भारत और ईरान के साझा हित हैं और दोनों ही यहाँ पर तालिबान और अल–कायदा के विरोधी हैं।

भारत ने अपनी पश्चिम एशिया नीति में सामरिक स्वायत्ता की नीति का प्रदर्शन किया है। पश्चिम एशिया के राजनीतिक–सामरिक समीकरण में कई ध्रुव हैं। अब भारत की नीति किसी एक ध्रुव के साथ सम्बद्ध न होकर सभी के साथ स्थिति के अनुरूप संबंध विकसित करने और सामरिक स्वायत्ता बनाए रखने की है। इस सामरिक स्वायत्ता को न केवल इज़रायल–फिलिस्तीन के संदर्भ में बल्कि ईरान–इज़रायल, सऊदीअरब–ईरान के संदर्भ में अपनायी गयी संतुलन की नीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। भारत–ईरान के बीच रक्षा सहयोग को इज़रायल अपनी सुरक्षा चिंता के विरोध में देखता था। उसे भय था कि भारत–इज़रायल रक्षा सहयोग में भारत को दी जाने वाली तकनीक कहीं ईरान के हाथ में न लग जाए। इज़रायल की सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में भारत ने ईरान से अपने संबंधो को रक्षा क्षेत्र में कम अवश्य किया है लेकिन ऊर्जा जरूरतों, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में ईरान के माध्यम से पहुँच बनाने और इस नजरिए से चाबाहर पोर्ट का विकास करने और अफगानिस्तान में आतंकवाद पर सहयोग को जारी रखा है। वस्तुतः भारत और ईरान दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ईरान भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ईरान भारत की ऊर्जा जरूरत को पूरा करता है। दोनों देशों में गैर–ऊर्जा व्यापार भी बढ़ा है। ईरान

के माध्यम से भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अपनी पहुँच बनाना चाहता है। इसी दृष्टि से भारत ईरान में चाबाहर पोर्ट का विकास के लिए 100 मिलियन डालर के निवेश की योजना बनाई है। ईरान से गैस के आयात की योजनाएँ अभी तक कार्यरूप नहीं ले सकी हैं। 2009 में भारत ने गैस पाइप लाइन से अपने को बाहर कर लेने के बाद ईरान–पाकिस्तान–भारत गैस पाइप लाइन अब अतीत का मुद्दा बन चुका है। अफगानिस्तान में दोनों देशों के साझा सामरिक हित हैं। दोनों ही तालिबान के विरोधी हैं। इस प्रकार भारत ने इज़रायल को भी समझाने की कोशिश की है कि भारत का ईरान से संपर्क इज़रायल के राष्ट्रीय हितों और उसकी सुरक्षा चिंताओं के विपरीत नहीं है।

भारत–इज़रायल सामरिक सम्बन्धों में पाकिस्तान कारक नकारात्मक भूमिका निभा सकने की संभावित क्षमता रखता है।[102] जून 2013 में इज़रायली समाचार पत्र 'हारेत्स' में छपी एक खबर के अनुसार एक ब्रिटिश सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इज़रायल ने पाकिस्तान और चार अरब राज्यों को रक्षा उपकरणों का निर्यात किया है।[103] इज़रायल ने पाकिस्तान को इज़रायली सैन्य तकनीक के हस्तांतरण के कथित समाचार का तत्काल खंडन किया।[104] इज़रायल के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 'इज़रायल पाकिस्तान को रक्षा उपकरण का निर्यात नहीं करता है' और 'इज़रायल ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा खतरे मे पड़े'।[105] इज़रायल द्वारा पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति करने की उक्त खबर भारत–इज़रायल सामरिक साझेदारी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।[106] यह सच है कि इजरायल और पाकिस्तान में राजनीतिक संपर्क बढ़ा है और इसी क्रम में 2005 में पाकिस्तान और इजरायल के विदेश मंत्रियों की तुर्की के इस्तांबुल में बैठक भी हुई थी। इज़रायल की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान से राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना हो जाये क्योंकि इससे इस्लामिक जगत में इज़रायल की स्वीकार्यता और औचित्य का भाव बढ़ेगा। निकट भविष्य में या एक दशक

में या इसके बाद भी यह संभव है कि इज़रायल और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधो की स्थापना हो जाय। एक परिकल्पना यह हो सकती है इज़रायल–पाकिस्तान में निकट भविष्य में राजनयिक संबंध स्थापित होते हैं तो भी इजरायल भारत के साथ आज की सामरिक गणना के हिसाब से अपने लाभदायक सामरिक सम्बन्धों के जोखिम की कीमत पर पाकिस्तान से सम्बन्धों का विकास एवं विस्तार एक सीमा के आगे नहीं करेगा। अधिक से अधिक संभावना यह हो सकती है कि इज़रायल अपनी सामरिक स्वायत्ता के तहत पाकिस्तान से राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के बाद केवल व्यापारिक, आर्थिक और गैर–सामरिक क्षेत्र में ही सहयोग को जारी रखे और संबंधो को कोई ऐसा सामरिक आयाम न दे जिससे भारत की सुरक्षा प्रभावित हो। पाकिस्तान के आतंक का केंद्र होने के कारण और इज़रायल की सुरक्षा चिंताओं के कारण भी इज़रायल को इसे कोई सामरिक–रक्षा तकनीक नहीं देना चाहिए।

भारत की इज़रायल समर्थक नीति का आशय यह नहीं है कि भारत पश्चिम एशिया के अन्य महत्वपूर्ण कर्ताओं की अवहेलना कर रहा है और उसने अपने समस्त अंडे एक ही टोकरी में रख देने की नीति को अपनाया है। भारत की पश्चिम एशिया नीति में एक संतुलन देखने को मिलता है। अब भारत ने किसी एक कर्ता के साथ सम्बद्ध होने की बजाय बहुमुखी संबद्धता की नीति पर बल दिया है जो कि भारत की बहू–वेक्टर उन्मुख नीति की ओर संकेत करता है। इससे भारत की सामरिक स्वायत्ता की नीति भी प्रतिबिम्बित होती है। भारत ने विदेश नीति निर्माण एवं राजनय में सामरिक स्वायत्ता पर बल दिया है। सामरिक स्वायत्तता का आशय बाहरी दबाव के बिना एवं राष्ट्रीय हितों का संरक्षण और संवर्धन करते हुए विदेश नीति निर्णय निर्माण में स्वतंत्र धारा का अनुसरण करना है। उत्तर–शीत युद्ध काल में पश्चिम एशिया में भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया है और विदेश नीति में सापेक्षिक सामरिक स्वायत्ता बनाए रखी है। भारत ने क्षेत्र, देश और मुद्दा विशेष

के आधार पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का प्रदर्शन किया है। पश्चिम एशिया के देशों में आंतरिक संघर्ष या दो–पक्षीय आपसी तनाव या क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति में भारत ने अहस्तक्षेपकारी एवं समान दूरी की नीति अपनायी। भारत ने पारस्परिक संवाद से संघर्ष के समाधान पर बल दिया। ईरान–सऊदी प्रतिस्पर्धा, ईरान–जीसीसी का आपसी संदेह, अरब–इजरायल संघर्ष, इज़रायल–फिलिस्तीन संघर्ष, इराक–सऊदीअरब मतभेद–गतिरोध, जीसीसी में आंतरिक मतभेद, सीरिया संघर्ष, यमन के राजनीतिक संकट आदि में भारत ने किसी का पक्ष न लेते हुए सामरिक स्वायत्ता एवं संतुलन–नीति का परिचय देते हुए इन सभी राज्यों से लाभदायक संबंध विकसित किए हैं। इज़रायल, ईरान, इराक और जीसीसी देशों में भारत के बहुआयामी निहित हितों को देखते हुए यह एक जरूरी रणनीति थी। किसी का पक्ष लेने की स्थिति में भारत के हित प्रभावित हो सकते थे। भारत ने परमाणु मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण में ईरान के खिलाफ मत देने के बावजूद ईरान से न केवल व्यापार एवं ऊर्जा सहयोग को जारी रखा बल्कि चाबाहर पोर्ट के विकास में भी रुचि व्यक्त की है। भारत ने इज़रायल से बहुआयामी पारस्परिक लाभदायक संबंध विकसित करने के साथ–साथ फिलिस्तीन मुद्दे पर अपना परंपरागत समर्थन जारी रखा है। भारत को तेल आपूर्ति के मामले में सऊदीअरब के बाद इराक का दूसरा स्थान है। भारत ने जीसीसी देशों से बहुआयामी सहयोग विकसित किया है।

पश्चिम एशिया के नए समीकरण में तीन ध्रुव उभरे हैं यथा सऊदी–मिस्र ध्रुव, तुर्की–क़तर ध्रुव और ईरान–सीरिया ध्रुव। भारत ने इन तीनों ध्रुवों के साथ लाभदायक संबंध विकसित किए हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण धुरी के रूप में विद्यमान सऊदी–मिस्र ध्रुव के साथ इज़रायल के संबंध काफी बेहतर हैं। पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति लगभग प्रवाह में और अनिश्चिततापूर्ण है। यहाँ क्षेत्रीय और क्षेत्रातीत शक्तियों के रूप में कई राज्य–कर्ता सक्रिय भूमिका

में हैं। इस स्थिति को देखते हुए भारत ने बड़ी सजगता से सामरिक स्वायत्ता की नीति पर बल देते हुए सामरिक स्थायित्व का समर्थन किया है ताकि उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और संवर्धन किया जा सके। भारत ने पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने सम्बन्धों को संतुलित किया है। पश्चिम एशिया में भारत ने इराक, सऊदी अरब, क़तर बहरीन, इज़रायल के साथ सम्बन्धों का विकास करते हुए ईरान से भी संबंधो का विकास करते हुए संतुलित विदेश नीति और सामरिक स्वायत्ता का परिचय दिया है।

इस क्षेत्र में संघर्ष, राजनीतिक परिवर्तन और अरब–वसंत के संबंध में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के अनुरूप सामरिक स्वायत्ता का परिचय दिया है। भारत ने पश्चिम एशिया में लोकतान्त्रिक जनाकांक्षाओं का समर्थन किया है लेकिन इस क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप द्वारा बलात परिवर्तन का समर्थन नहीं किया है। संप्रभु राज्य के आंतरिक मामले में अहस्तक्षेप की नीति भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धान्त रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति में भारत ने किसी पक्ष का समर्थन न करते हुए संवाद एवं वार्ता द्वारा संघर्ष समाधान पर बल दिया है।

इस प्रकार उत्तर–शीतयुद्ध काल में भारत ने सामरिक स्वायत्ता की नीति पर बल देते हुए इज़रायल से समझदारीपूर्ण परस्परिक लाभदायक संबंध विकसित किए हैं और दोनों ही देश कतिपय असहज विंदुओं पर एक दूसरे को आश्वस्त करते हुए आपसी सम्बन्धों को बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर पिछले दो दशकों की राजनयिक यात्रा में दोनों देशों ने बहुपक्षीय साझेदारी के सम्बन्धों का विकास किया है। भारत–इज़रायल संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं हैं और न ही किसी तीसरे देश के प्रभाव के कारक से प्रभावित हैं। भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे के प्रति परंपरागत समर्थन को बनाए रखते हुए इज़रायल से करीबी पारस्परिक लाभदायक मित्रतापूर्ण सम्बन्धों की स्थापना की है। भारत ने यथार्थवादी प्रिज्म द्वारा प्रस्तावित रणनीति के अनुरूप इज़रायल से किसी

संधि का निर्माण नहीं किया है बल्कि सामरिक साझेदारी का विकास किया है। दोनों देशों का आपसी सहयोग हितों की पारस्परिकता के आधार पर विकसित हो रहा है। भारत की इज़रायल नीति के स्वरूप में जो परिवर्तन परिलक्षित हुए है उनसे यह भी दर्शित होता है कि भारत की फिलिस्तीन समर्थन की परंपरागत नीति की निरंतरता पर गांधी–नेहरूवादी प्रिज़न का प्रभाव शेष है लेकिन भारत की इजरायल नीति में आया गुणात्मक परिवर्तन यथार्थवादी प्रिज्म की ओर झुकाव को प्रतिबिम्बित करता है। अब अधिक संभावना इस बात की है कि भारत की फिलिस्तीन समर्थन की परंपरागत नीति को यथावत बनाए रखते हुए फिलिस्तीन मुद्दे को भारत–इज़रायल संबंधो के गहन विकास में बाधक नहीं बनने दिया जाएगा। साथ ही इज़रायल के साथ बहुआयामी संबंध और सहयोग को नवीन आयाम देते हुए गहनता को विकसित करते हुए दो–पक्षीय संबंधो का प्रोफाइल सार्वजनिक रूप से उच्च किया जाएगा।

ENDNOTES

1. For the details of India-Israel relations in post cold war period see: P.R. Kumaraswamy, "India and Israel: Evolving Strategic Partnership", Mideast Security and Policy Studies, No. 40, September 1998; Efraim Inbar and Alvite Singh Ningthoujam, "Indo-Israeli Defense Cooperation in the Twenty-First Century", Mideast Security and Policy Studies No. 93, January 2012; PR Kumaraswamy, "The Maturation of Indo-Israeli Ties: Israel in the World", Middle East Quarterly, Spring 2013, pp 39-48,at http://www.meforum.org/3494/india-israel-ties; Farah Naaz, "Indo-Israel Relations: An Evolutionary Perspective",at http://www.idsa-india.org/an-may9-5.html
2. For the brief discussion of the debate regarding Gandhi and Zionism see: A. K. Ramakrishnan, "Mahatma Gandhi Rejected Zionism", August 15, 2001, Wisdom Fund, http://www.twf.org/News/Y2001/0815-GandhiZionism.html; E. S. Reddy, "Gandhi, The Jews and Palestine: A Collection of Articles, Speeches, Letters and Interviews", at http://www.gandhiserve.org/information/writings_online/articles/gandhi_jews_palestine.html; "Gandhi: Zionism and anti-Semitism", in Homer A. Jack (ed), *The Gandhi Reader: A Source Book of His Life and Writings*, Homer (New York, AMS Press, 1956), pp. 317-322 at http://globalwebpost.com/farooqm/study_res/gandhi/gandhi_zionism.html
3. Gandhi, "The Jews", Harijan, November 26, 1938, at http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/JewsGandhi.html
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Benny Morris, "Einstein's other theory", The Guardian, February 16, 2995, at http://www.theguardian.com/world/2005/feb/16/israel.india
8. Mani Shankar Aiyar, "Modi's Overtures to Israel are Deeply Degerous", NDTV, March 24, 2015, at http://www.ndtv.com/opinion/modis-overtures-to-israel-are-deeply-dangerous-749042
9. Ilan Ben Zion, "Former Indian Cabinet Minister:'Impossible to have good moral relations with Israel'", Times of Israel, February 18, 2014, at http://www.timesofisrael.com/former-indian-mp-impossible-to-have-a-good-moral-relations-with-israel/
10. Mani Shankar Aiyar, "Modi's Overtures to Israel are Deeply Degerous", NDTV, March 24, 2015, at http://www.ndtv.com/opinion/modis-overtures-to-israel-are-deeply-dangerous-749042

11. Mani Shankar Aiyar, "India's government is cowering behind the BRICS position on the conflict", Indian Express, July 23, 2014, at http://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-gaza-evasion/

12. Mani Shankar Aiyar, "Modi's Overtures to Israel are Deeply Degerous", NDTV, March 24, 2015, at http://www.ndtv.com/opinion/modis-overtures-to-israel-are-deeply-dangerous-749042

13. "Why Modi's India aligns more closely with Israel than with Palestinians", Aljazeera, August 3., 2014, at http://america.aljazeera.com/articles/2014/8/3/modi-israel-relations.html

14. Ibid.

15. Isabelle Saint-Mezard, "India and Israel: an unlikely alliance: From Antipathy to Military Cooperation", at HTTP://MONDEDIPLO.COM/2010/11/11INDIAISRAEL; Louise Tillin, "US-Israel-India: Strategic axis?", BBC, at http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3092726.stm

16. Dr Subramanian Swamy speech to express Solidarity with ISRAEL, 3 August 2014, available at https://www.youtube.com/watch?v=lzcqj8XFiVE

17. For the brief discussion of Marxist/Soviet perspective on Zionism and Israel see: Sergeyev, Sergei, "Zionism, Instrument of Aggressive Imperialist Circles", in P. N. Fedoseyev and others (ed.), *The Palestine Problem: Aggression, Resistance, Way of Settlement*, USSR Academy of Science, Moscow, 1948; Sharif, Walid, "Soviet Marxism and Zionism", *Journal of Palestine Studies*, Beirut, Spring 1977, no. 6 (3).

18. Sharif, Walid, "Soviet Marxism and Zionism", Journal of Palestine Studies, Spring 1977, no. 6 (3), p. 78.

19. Ibid. p. 79.

20. Schechtman, J. B., 'The U.S.S.R., Zionism and Israel' in Lionel Kochan (Ed.) *The Jews in Soviet Russia since 1917*, (London: Oxford University Press, 1970), p. 98.

21. Orbach, William, "A Periodization of Soviet Policy Towards the Jews", *Soviet Jewish Affairs*, (London), Vol. 12, no. 3, 1982, p. 60; see also Hashim S. H. Behbehani, *The Soviet Union and Arab Nationalism, 1917-1966*, (London: KPI Ltd., 1986), p. 20.

22. "Surjeet Writes to PM On Sharon Visit", Press Release of CPI (M), September 6, 2003, at http://cpim.org/content/surjeet-writes-pm-sharon-visit

23. "Gaza Attack: Government Stand Pro-Israeli", Press Statement of CPI(M), July 17, 2014, at http://www.cpim.org/content/gaza-attack-government-stand-pro-israeli

24. “Stop funding Israel’s war on Palestine, CPI-M tells Modi government”, Zee News, December 29, 2014, http://zeenews.india.com/news/india/stop-funding-israels-war-on-palestine-cpi-m-tells-modi-government_1522169.html

25. “Modi’s Israel visit amounts to abandoning Palestine: CPI-M”, Zee News, June 4, 2015, at http://zeenews.india.com/news/india/modis-israel-visit-amounts-to-abandoning-palestine-cpi-m_1607440.html

26. “On Strategic Alliance With Israel”, Press Statement of CPI (M), May 11, 20013, available at http://cpim.org/content/strategic-alliance-israel

27. “Left Parties on UPA Govt completing four years”, Left Parties Statement on May 23, 2008, available at http://cpim.org/content/left-parties-upa-govt-completing-four-years

28. Kautilya, *Arthshastra*, ed. By L. N. Rangrajan (New Delhi, Penguin, 1992).

29. For the detailed analysis of Chanakya’s thought see George Modelski, “Kautlya; Foreign Policy and International Systen in Ancient Hindu World”, American Political Science Review, Vol. 58, no. 3, September 1964, pp. 549-560; see also Rasheed Us Zaman, “Kautilya:The Strategic Thinker and Indian Strategic Culture”, *Comparativ Strategy,* Vol. 25, 2006, pp. 231-247;

30. For the discussion of Cultural Realism, see Alaistair Johnston, *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Ming China,* (Princeton, Princeton University Press, 1995).

31. For the detailed discussion of structural Realism, see Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, (New York: McGrawHill, 1979).

32. P. R. Kumaraswamy, *India’s Israel Policy*, Columbia University Press, 2010.

33. ‘Gandhi, Mohandas Karamchand”, Jewish Virtual Library, at http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0007_0_07046.html

34. Ibid.

35. Ibid.

36. Ibid.

37. For the details of India’s West Asia policy Under Prime Minister Jawaharlal Nehru see Najma Heptulla, *The Indo-West Asian Relations: The Nehru Era* (New Delhi, South Asia Books, 1992)

38. Benny Morris, op. cit. Rasheed Uz Zaman, “Kautilya: The Indian Strategic

Thinker and Indian Strategic Culture", *Comparative Strategy*, Vol. 25, 2006, pp. 231-247.

39. "India condemns the suicide bomb attack on Tel Aviv on 1st June which led to loss of life and injuries to a large number of innocent people", June 04, 2001, http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/19010/India_condemns_the_suicide_bomb_attack_on_Tel_Aviv_on_1st_June_which_led_to_loss_of_life_and_injuries_to_a_large_number_of_innocent_people

40. Fourth Meeting of the India-Israel Joint Working Group on Counter Terrorism and First Round of Consultations on Disarmament Issues (New Delhi, November 29 - December 2, 2004), December 02, 2004, at http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/7360/Fourth_Meeting_of_the_IndiaIsrael_Joint_Working_Group_on_Counter_Terrorism_and_First_Round_of_Consultations_on_Disarmament_Issues_New_Delhi_November_2

41. "Statement by Official Spokesperson on abduction of Israeli soldier at Kerem Shalom crossing near Gaza", June 27, 2006, at http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/4227/Statement_by_Official_Spokesperson_on_abduction_of_Israeli_soldier_at_Kerem_Shalom_crossing_near_Gaza

42. "Statement by Official Spokesperson on the tension at the Israel-Lebanon border", July 13, 2006, at http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/4181/Statement_by_Official_Spokesperson_on_the_tension_at_the_IsraelLebanon_border

43. "We continue to remain gravely concerned at the situation in the West Asia", May 24, 2001, at http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/10523/We_continue_to_remain_gravely_concerned_at_the_situation_in_the_West_Asia

44. Press Statement, April 18, 2002, at http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/13487/Press_Statement

45. "India Expresses Concern At Developments In West Asia" September 23, 2002, at http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/18958/India_Expresses_Concern_At_Developments_In_West_Asia

46. "Statement by Official Spokesperson on the recent escalation of violence in West Asia", March 07, 2003,at http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/9171/Statement_by_Official_Spokesperson_on_the_recent_escalation_of_violence_in_West_Asia

47. "Statement by the Official Spokesman on the large scale demolition of homes in the Rafah Palestinian refugee camp in Gaza by the Israeli Defence Force", May 20, 2004, http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/7634/Statement_by_the_Official_Spokesman_on_the_large_scale_demolition_of_

homes_in_the_Rafah_Palestinian_refugee_camp_in_Gaza_by_the_Israeli_Defence_Force

48. "Statement by Shri E. Ahamed, Hon'ble Minister of State for External Affairs on the escalation of violence in Northern Gaza", October 05, 2004, at http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/7401/Statement_by_Shri_E_Ahamed_Honble_Minister_of_State_for_External_Affairs_on_the_escalation_of_violence_in_Northern_Gaza 49. "Statement by Official Spokesperson on the killing of innocent civilians in Gaza by the Israeli Defence Forces", June 12, 2006, at http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/4416/Statement_by_Official_Spokesperson_on_the_killing_of_innocent_civilians_in_Gaza_by_the_Israeli_Defence_Forces

50. "Statement by Official Spokesperson on the tension at the Israel-Lebanon border", July 13, 2006, at http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/4181/Statement_by_Official_Spokesperson_on_the_tension_at_the_IsraelLebanon_border

51. "Statement by Official Spokesperson on situation in Gaza", January 04, 2009, at http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/1573/Statement_by_Official_Spokesperson_on_situation_in_Gaza

52. "Official Spokesperson's response to a media question on violence in Gaza", November 18, 2012, at http://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/20823/Official_Spokespersons_response_to_a_media_question_on_violence_in_Gaza

53. P. R. Kumaraswamy, "The Maturation of Indo-Israeli Ties Israel in the World", Middle East Quarterly, Spring 2013, pp. 39-48, at http://www.meforum.org/3494/india-israel-ties

54. Suhasini Haidar, "Modi to meet Netanyahu; marks shift in Indian policy", The Hindu, September 29, 2014, http://www.thehindu.com/news/national/prime-minister-narendra-modis-visit-to-us/article6454837.ece?ref=relatedNews

55. Herb keinon, "Indo-Israel ties on the march", Jerusalem Post, September 29, 2014, at http://www.jpost.com/Israel-News/Indo-Israel-ties-on-the-march-376555

56. Herb Keinon, "Netanyahu meeting with Indian PM Modi signals 'increased Israeli-Indian cooperation'", Jerusalem Post, September 28, 2014, at http://www.jpost.com/International/Netanyahu-meeting-with-Indian-PM-Modi-signals-increased-Israeli-Indian-cooperation-376464

57. Suhasini Haidar, "Modi to be first Indian PM in Israel", June 1, 2015, Times of India, at http://www.thehindu.com/news/national/modi-to-be-first-indian-pm-in-israel/article7268929.ece?ref=relatedNews

58. “Narendra Modi will be first Indian PM to visit Israel and Palestine”, Times of India, June 1, 2015, at http://timesofindia.indiatimes.com/india/Narendra-Modi-will-be-first-Indian-PM-to-visit-Israel-and-Palestine/articleshow/47491228.cms

59. “India-Israel defence ties ‘out of closet’ now”, Times of India, February 18, 2015, at http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-Israel-defence-ties-out-of-closet-now/articleshow/46290751.cms

60. “No change in India`s policy on Palestine: Sushma Swaraj”, Zee News, July 21, 2014, at http://zeenews.india.com/news/nation/no-change-in-indias-policy-on-palestine-sushma-swaraj_949094.html

61. “India Backs Anti-Israel Vote: Can’t Support Violation of International Norms, Say Sources”, NDTV, July 24, 2014, at http://www.ndtv.com/article/india/india-backs-anti-israel-vote-can-t-support-violation-of-international-norms-say-sources-564142

62. Suhasini Haidar, “Modi to meet Netanyahu; marks shift in Indian policy”, The Hindu, September 29, 2014, http://www.thehindu.com/news/national/prime-minister-narendra-modis-visit-to-us/article6454837.ece?ref=relatedNews

63. Ibid.

64. Ibid.

65. “In a first, India refuses to vote against Israel at UN”, Times of India, July 4, 2015, at http://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/In-a-first-India-refuses-to-vote-against-Israel-at-UN/articleshow/47932142.cms

66. “Official Spokesperson’s response to a question on India’s vote on Resolution A/HRC/29/L.35 in the Human Rights Council”, MEA Media Briefings, July 3, 2015, at http://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/25425/Official_Spokespersons_response_to_a_question_on_Indias_vote_on_Resolution_AHRC29L35_in_the_Human_Rights_Council

67. Amit Baruah, “India may end support to Palestine at U.N.”, The Hindu, December 22, http://www.thehindu.com/news/national/india-may-end-support-to-palestine-at-un/article6713364.ece?homepage=true

68. Ibid.

69. “India’s stand at UNHRC a qualitative leap in ties, Israel says”, Times of India, July 8, 2015, at http://timesofindia.indiatimes.com/india/Indias-stand-at-UNHRC-a-qualitative-leap-in-ties-Israel-says/articleshow/47990509.cms?

70. Nidhi Rajdan, “On Eve of Gaza Vote, PM Narendra Modi Got a Call

From Israel Counterpart Benjamin Netanyahu", NDTV, July 6, 2015, at http://www.ndtv.com/india-news/israeli-pm-benjamin-netanyahu-called-pm-narendra-modi-on-eve-of-un-voting-on-gaza-india-abstained-778413?ndtv_related

71. "UNHRC vote: Palestine asks India to explain why it abstained", Indian Express, July 9, 2015, at http://indianexpress.com/article/india/india-others/unhrc-votepalestine-asks-india-to-explain-why-it-abstained/

72. "India spikes US' Javelin missiles for Israel's 'Spike'", Economic Times, October 26, 2014, at http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-10-26/news/55446711_1_rafael-advanced-defence-systems-israeli-missile-drdo-chief

73. Amos Harel, "Sisters in arms: The burgeoning defense trade between Israel and India", Haaretz, February 22, 2014, at http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.575486

74. "India, Israel discuss defence deals", Business Standard, June 30, 2014, at http://www.business-standard.com/article/pti-stories/india-israel-discuss-defence-deals-114063000997_1.html

75. "India spikes US' Javelin missiles for Israel's 'Spike'", Economic Times, October 26, 2014, at http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-10-26/news/55446711_1_rafael-advanced-defence-systems-israeli-missile-drdo-chief

76. "India spurns US offer and purchases guided missiles from Israel for $525m", The Guardian, October 25, 2014, at http://www.theguardian.com/world/2014/oct/25/india-purchases-guided-spike-missiles-israel

77. "Israel, India successfully test flagship anti-missile system", The Haaretz, November 11, 2014, at http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.625754

78. "India, Israel joint venture LR SAM missile successfully tested", The Economic Times, November 11, 2014, at http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-11-10/news/55955944_1_range-surface-indian-army-air-missile

79. "DRDO Greets New Defence Minister With Successful LRSAM Test" The Indian Express, November 11, 2014, at http://www.newindianexpress.com/nation/DRDO-Greets-New-Defence-Minister-With-Successful-LRSAM-Test/2014/11/10/article2517040.ece

80. "Overview of India-Israel Bilateral Trade and Economic Relations", at http://itrade.gov.il/india/israel-india/

81. "India-Israel free trade agreement to boost trade volume", June 26, 2013, The Economic Times, at http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-06-26/news/40207121_1_the-fta-trade-agreement-trade-volume

82. "India, Israel inching closer to signing FTA: Israeli envoy", June 13 2013, The Times of India, at http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/India-Israel-inching-closer-to-signing-FTA-Israeli-envoy/articleshow/2-0578136.cms

83. "Israel-India Cooperation in Agriculture", at http://embassies.gov.il/delhi/Departments/Pages/Agricultural%20Afairs.aspx

84. "Revolutionising Indian farming - with Israeli technology", Business Standard, March 2, 2014, at http://www.business-standard.com/article/news-ians/revolutionising-indian-farming-with-israeli-technology-agriculture-feature-with-images-114030200232_1.html

85. Ibid.

86. India, Israel extend agricultural cooperation action plan, The Times of India, September 19, 2014, at http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-Israel-extend-agricultural-cooperation-action-plan/articleshow/42847157.cms

87. "Israel to showcase its agro excellence in 10 Indian states by 2015", The Times of India, October 9, 2013, at http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Israel-to-showcase-its-agro-excellence-in-10-Indian-states-by-2015/articleshow/23735020.cms

88. Nicolas Blarel, "Redefining India's Grand Strategy? The Evolving Nature of India's Israel Policy" in Kanti Bajpai, Saira Basit, V. Krishnappa (ed.) India's Grand Strategy: History, Theory, Cases, (New Delhi, Routledge, 2014), pp. 449-478.

89 Ibid. p. 462.

90. For the details of the Soviet Role in the emergence of Israel see: Yaacov Ro'i, "Soviet Policies and Attitudes Toward Israel", 1948-1978-An Overview, *Soviet Jewish Affairs*, Vol. 8, no. 1, 1978; Gabriel Gorodetsky, "The Soviet Union and the Creation of the State of Israel" (Research Paper, Tel Aviv University, 2001); Rumy Hasan, The Soviet hand in Israel, Al-ahram Weekly, 15 - 21 May 2008, Issue No. 897 at http://weekly.ahram.org.eg/2008/897/op6.htm

91. For the details of the Soviet Policy Initiatives towards West Asia see: Galia Golan, *Soviet Policies in the Middle East: from World War Two to Gorbachev*, (Cambridge, Cambridge University Press, 1990); Gromyko,

A. and Ponomarev, B. N. (ed.), *Soviet Foreign Policy 1945-1980*, Moscow, July, 1967, Volume II, (Progress Publishers, 1981); Anoop Kumar Gupta, "The Soviet Union's Policy Towards Arab-Israel Conflict, 1967-78", Doctoral thesis submitted at Centre for Russian and Central Asian Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi in 2002; Amnon Sella, "Changes in Soviet Political-Military Policy in the Middle East after 1973", Research Paper No. 25, The Soviet and East European Research Centre, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, 1977.

92. James A. Phillips, "Gorbachev's "Newthink" on the Middle East", *Midstream*, August-September-1989, Vol. 35, No. 6, NewYork, pp. 12-16.

93. Nicolas Blarel, "Redefining India's Grand Strategy? The Evolving Nature of India's Israel Policy", in Kanti Bajpai, Saira Basit and V. Krishnappa, *India's Grand Strategy*, (New DelhiRoutledge, 2014), pp. 464, 468.

94. "Nehru's Anti-israel Remarks Evoke Reply by Ben Gurion in Knesset", JTA, The Global Jewish News Source, May 22, 1958, at http://www.jta.org/1958/05/22/archive/nehrus-anti-israel-remarks-evoke-reply-by-ben-gurion-in-knesset

95. Ibid.

96. Ibid.

97. Jayakrishnan Nair, "Einstein, Nehru and Israel" Foreign Affairs, February 18, 2005, at HTTP://VARNAM.NATIONALINTEREST.IN/2005/02/EINSTEIN_NEHRU_AND_ISRAEL/

98. "For Israel, China's a trading partner, India a strategic one", Times of India, November 18, 2014, at http://timesofindia.indiatimes.com/india/For-Israel-Chinas-a-trading-partner-India-a-strategic-one/articleshow/45183357.cms

99 ईरान के प्रति इसरायली रुख और ईरान–इसरायल सम्बन्धों के लिए देखें अनूप कुमार गुप्ता, "ईरान समझौताः इज़रायल की नजरें टेढी", डीएलए, दिसंबर 4, 2013; अनूप कुमार गुप्ता, "ईरान और इज़रायल में बढती तल्खी", डीएलए, मई 18, 2012; ईरान परमाणु समस्या और संबन्धित परमाणु संवाद के संक्षिप्त विवरण लिए देखें: अनूप कुमार गुप्ता, "विस्फोटक स्थिति में ईरान समस्या", डीएलए, अप्रैल 16, 2012; अनूप कुमार गुप्ता, "ईरान से परमाणु संवाद के मायने", डीएलए, अक्तूबर 26, 2013

100. "India cannot stay neutral towards Iran: Israel Prez", Zee News, June 23, 2013, at http://zeenews.india.com/news/world/india-cannot-stay-neutral-towards-iran-israel-prez_857104.html

101. Narain D. Batra, "Complicated relationship: India needs both Israel & Iran", The Economic Times, February 19, 2012,at http://articles.

economictimes.indiatimes.com/2012-02-19/news/31077135_1_chabahar-port-india-and-israel-pranab-mukherjee

102. अनूप कुमार गुप्ता, "पाक–इज़रायल सम्बन्धों का मतलब", दैनिक जागरण, सितंबर 28, 2005

103. Aluf Benn, "Israel selling military wares to Mideast countries, Britain says", The Haaretz, June 11, 2013, at http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.528993

104. Aluf Benn and Gili Cohen, "Following Haaretz report, Israel denies selling arms to Pakistan", The Haaretz, June 12, 2013, at http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.529308

105. "Will not do anything to undermine India's security: Israel" The Hindu, June 13, 2013, at http://www.thehindu.com/news/international/world/will-not-do-anything-to-undermine-indias-security-israel/article4809881.ece;

106. "Pakistan military technology row threatens Israel's strategic relationship with India" The Telegraph, June 13, 2013, at http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/10119393/Pakistan-military-technology-row-threatens-Israels-strategic-relationship-with-India.html

डा॰ अनूप कुमार गुप्ता विदेश नीति, सुरक्षा एवं सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। वह एक स्वतंत्र अध्येता एवं स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। इन्होने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से राजनीति–विज्ञान में परा–स्नातक करने के उपरांत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में पी॰ एच॰ डी॰ की उपाधि ग्रहण की। इन्होने जे॰ एन॰ यू॰ के वित्तीय समर्थन से वर्ष 2001 में अरब–इज़रायल संघर्श पर शोध कार्य पूर्ण करने हेतु इज़रायल यात्रा की। वर्ष 2002–03 में इज़रायल सरकार स्कालरशिप कार्यक्रम के तहत वह हिब्रू विश्वविद्यालय, जेरूसलेम, इज़रायल में विजिटिंग शोधार्थी के रूप में शोधरत रह चुके हैं। वह पश्चिम एशिया में संघर्ष विश्लेशण एवं समाधान, रूस की पश्चिम एशिया नीति और भारत की विदेशनीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के विशेषज्ञ है। इन विषयों पर वह विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और शोध जर्नल में निरंतर रचनात्मक लेखन करते हैं। अपने इज़रायल प्रवास के दौरान वह इज़रायल और फिलिस्तीनी राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, नई दिल्ली को समाचार प्रेषण करते रहे हैं।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखम्बा रोड़,
नई दिल्ली-110005

ISBN 978-93-83445-28-8
9 789383 445288